संसद में बहस
vke ctV 2010&2011
अरुण जेटली......................... 5
प्रभात झा................................ 7
यशवंत सिन्हा........................ 9
निशिकांत दुबे........................ 10
efgyk vkj{k.k foèk;d
अरुण जेटली......................... 12
माया सिंह............................. 14
लेख
अंध मोदी–विरोध का अर्थ
एस. शंकर...................... 22
गरीबों की गिनती में गड़बड़झाला
शांता कुमार.................... 23
भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित
अनुभव और ऊर्जा.................. 15
राज्यों से
महाराष्ट्र.................................. 25
दिल्ली.................................... 26
बिहार..................................... 27
मध्य प्रदेश.............................. 28
उत्तराखंड, कर्नाटक................. 30

सम्पादक
çHkkr >k] lkal n
सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kek
lath o dekj flUgk
पृष्ठ संयोजन
/keUæ dk'ky
fodkl luh
सम्पर्क
Mk- eqd thl Lefr U;kl
ihih&66] lcze.;e Hkkjrh ekxl
ubl fnYyh&110003
Qku u- +91¼11½&23381428
QDl % +91¼11½&23387887
lnL;rk gr| % +91¼11½&23005700
सदस्यता शुल्क
okf"kd 100#- | f=okf"kd 250#-
e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

{ पापाची वासना नको देऊ डोळा, त्याहुन आंधळा बराच मीं।
पाप की दुनिया को देखने से अंधा हो जाना अच्छा है। }

&lar rqdkjke

lEikndh;

सबसे बड़ा दायित्व ''कार्यकर्ता''

व्यक्ति निमित्त होता है, पर चाहे वह जितना बड़ा हो, संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। अन्य राजनीतिक दलों में यह विशेषता हो न हो, पर भाजपा में यह विशेषता शत–प्रतिशत है। राजनाथजी गए, गडकरीजी आ गए। व्यक्ति का परिवर्तन व्यवस्था से जुड़ा होता है और संगठन ने जिसको व्यवस्था दी, उस पर सारा संगठन विश्वास करने लगता है। राजनीतिक कप्तान का परिवर्तन जिस खेल भावना से भाजपा में हुआ वह राजनीति में अपने–आप में एक मिसाल है। चाहे अटलजी हों, आडवाणीजी हों, डॉ. जोशी हों या फिर राजनाथजी हों, दायित्व मुक्त होने के बाद कार्यकर्ता उतना ही प्रेम उड़ेलते हैं। परिवर्तन व्यवस्था है, पर हर परिवर्तन की एक अवस्था होती है। अवस्था चाहे जितनी बड़ी हो वह व्यवस्था के अंतर्गत ही अपने को बांध लेते है। यही संगठन है।

राष्ट्रीय अध्यक्षजी ने जो टीम बनाई है, उसमें इंदौर की बानगी साफ–साफ झलक रही है। इस टीम में अनुभव और ऊर्जा का अद्‌भुत संगम है। गांव–शहर में अनुपात है। सामाजिक समरसता है। 33 प्रतिशत महिला आरक्षण घोषणा का यथार्थ भी देखा जा सकता है। समाज यदि गौर से देखे तो कोई यह नहीं कह सकता कि इस टीम में वह नहीं है। टीम जब कहते हैं तो उसे संख्या में बांधनी होती है और जब संख्या आ जाती है तो निर्णय भी संख्या से बंध जाता है। इस सच से कौन इंकार कर सकता है कि पद उतने हो नहीं सकते, जितने लोग काबिल हैं और जितने लोग काबिल है उस अनुपात में पद भी नहीं बढ़ाए जा सकते। यहीं पर एक शब्द आता है 'कार्यकर्ता'। जो दल में सदैव बनकर रहा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र की दिक्कत यही है कि लोग कार्यकर्ता बनकर नहीं रहना चाहते। पदारूढ़ तो कोई हो सकता है पर कार्यकर्ता बनकर दल में काम करने की प्रबलतम इच्छा धीरे–धीरे कम होती जा रही है। आज जो पद पर हैं क्या वे सदैव बने रहेंगे या जो पद पर हैं वे कभी नहीं आएंगे। जो पदारूढ़ होता है उसे किसी न किसी दिन उतरना होता है। अंतर इतना है कि आप पदारूढ़ होकर यदि कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं तो कार्यकर्ता आपको अपने से भिन्न नहीं पाता है और यदि आप पदारूढ़ होकर 'कार्यकर्ता' का सत्व और तत्व छोड़ देते हैं तो भला वह कार्यकर्ता आपको अपना कैसे कह सकता है।

राजनैतिक क्षेत्र की प्रकृति धीरे–धीरे बदलती जा रही है। कल जैसी राजनीति आज नहीं है और आज जैसी राजनीति कल नहीं

रहेगी। अतः भाजपा जैसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं को अपने–अपने स्थान पर सदैव समझ बढ़ाने की कवायद करते रहना होगा। जो रियाज करता रहेगा, वही समाज को बेहतर सुर दे सकता है। कार्यकर्ता बनकर जीने का रियाज सदैव जारी रहना चाहिए। रियाज साधना है और साध्य की प्राप्ति के लिए साधना आवश्यक है। राजा जनक को विदेह इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपने को देह–मोह से मुक्त कर लिया था। राजनीति में वैदेहियों की कमी हो गयी है। कमी होना तो ठीक है पर यदि वैदेही में मोह जग जाए तो फिर कुछ नहीं बचता है। सबकी अपनी–अपनी मर्यादाएं हैं। लक्ष्मण रेखाएं हैं। हम सबने अपने–अपने स्थान पर इस बात को याद रखा तो शायद जिसलिए हमने राजनीति का मार्ग चुना है उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें सरलता से हो पाएगी।

भाजपा का वर्तमान चुनौतियों भरा डगर है। संगठन ने एक ऐसे पतवार के हाथ में बागडोर सौंपी है जिसमें सामूहिकता है, नैतिकता है, प्रामाणिकता है, शुचिता है। पतवार के खेवैया का जब ऐसा गुण है तो उसके टीम के प्रत्येक सदस्य को ऐसे ही गुणों से सुसज्जित होना होगा क्योंकि 21वीं सदी में वही टिक पाएगा जिसमें प्रतिभा होगी, सत्यता होगी, व्यवहारकुशलता होगी, विश्वसनीयता होगी, प्रतिबद्धता होगी और पारदर्शिता होगी। इस दृष्टि से जब हम राजनीतिक दलों पर पैनी निगाह फेरते हैं तो भाजपा के सिवाय कहीं भी कोई टिमटिमाता दीया नहीं दिखता।

अतः भाजपा के नव–नेतृत्व को आंधी और तूफान के बीच न केवल टिमटिमाना है बल्कि अपने को जलाना होगा। ■

माधोपुर : डा. मुखर्जी प्रतिमा का अनावरण

धारा ३७० को खत्म करना ही डा. मुकर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि : गडकरी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने रावी नदी के तट पर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि श्री मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जम्मू–कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा आज देश के राष्ट्रवादी आंदोलन का स्वर्णिम दिन है। आर.एस.एस. और भाजपा ने देश की जनता को राष्ट्रभक्ति के संस्कार दिए हैं। यह स्मारक इसका प्रतीक है और देश के करोड़ों नौजवान इस स्थान से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेंगे। वर्तमान केन्द्र की सरकार विदेशी दबाव में काम कर रही है। यह सरकार अमेरिका परस्त सरकार है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उसके बावजूद भी सरकार पाकिस्तान से बातचीत कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि

पाकिस्तान से बातचीत का कोई अर्थ नहीं, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद समाप्त नहीं करता। मैं पंजाब सरकार का आभारी हूं, जिन्होंने राष्ट्रवाद के मसीहा श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित की।

इस अवसर पर अपार जन समूह को संबोधित करते हुए श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि यह स्मारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों की याद दिलाएगा। अगर सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो यह देश अंग्रेजों की साजिश का शिकार होकर विघटित हो सकता था। श्री मुखर्जी ने देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान लेकर आंदोलन किया और अपना बलिदान दिया और आज उनके बलिदान की वजह से कश्मीर में दो प्रधान का कानून नहीं है मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि एक दिन कश्मीर में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्थापित होगा।

इस अवसर पर रा.स्व.संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने कहा कि श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से भारत के लगातार हो रहे विभाजन की प्रक्रिया रूकी। कश्मीर में उग्रवाद फैलाने वालों को सहानुभूति मिलती है लेकिन, जो कश्मीरी पंडित आज कश्मीर से इस देश में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं, उनकी घर वापसी की बात नहीं हो रही है। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने छोटी पार्टी के नेता होते हुए भी कश्मीर के विभाजन की प्रक्रिया को रोका। कश्मीर भारत में रहे यह केवल कश्मीर का स्थानीय मुद्दा नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के मान–सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि देश के शहीदों को किसी प्रांत या मज़हब के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो लोग भाषा, प्रांत, सांप्रदाय, के आधार पर घृणा का व्यवहार कर रहे हैं, वह देश की एकता के हित में नहीं है। ■

राज्यसभा

महंगाई बढ़ाने वाला बजट : भाजपा

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने संसद में 2010–11 के लिए आम बजट पेश किया। विपक्षी दलों ने बजट को आंकड़ों की बाजीगरी और महंगाई की समस्या व किसानों की अनदेखी करने वाला बताया। संसद के दोनों सदनों–राज्यसभा और लोकसभा में आम बजट– 2010–11 पर हुई चर्चा में भाजपा सांसदों ने भाग लेते हुए बजट को आम आदमी के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की घोषणा से हर चीज के दाम बढ़ेंगे। जनता ने इस बजट से कुछ राहत की उम्मीद की थी लेकिन उसकी आशाओं पर कुठाराघात हुआ है। हम यहां भाजपा सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:

अरुण जेटली

राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने, चर्चा शुरू करते हुए, कहा वित्त मंत्री के पास इस वर्ष एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि उन्हें कतिपय विशिष्ट वैश्विक घटनाक्रमों – आर्थिक मंदी, सूखे के कारण कृषि संबंधी संकट और विशेषकर खाद्यान्न कीमतों में वृद्धि के चलते बजट पेश करना था। राष्ट्र की यह उम्मीद थी कि बजट इन मुद्दों का समाधान करने के लिए एक नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। परन्तु इसका विश्लेषण करने पर मैं इस बजट से प्रसन्न नहीं हूं।

इस सभा में थोक मूल्य सूचकांक, जोकि फरवरी में 8.56 प्रतिशत था, पर अपनी चिंता व्यक्त की। खाद्यान्न मुद्रास्फीति अब लगभग 19 प्रतिशत है। अब हम वास्तव में किस तरह, इस स्थिति के दृष्टिगत, बजट को कसौटी पर रखते हैं? क्या सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध हैं? यदि कमी है, तो आपको उसे उपलब्ध कराना चाहिए। हमारे यहां पहले भी सूखा पड़ा है लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। चूंकि उनके सामने राजस्व घाटा की बड़ी समस्या भी मौजूद रही है, इसलिए मूल्यवर्धित कर भी अभी 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। एक विकल्प उत्पाद शुल्क में तीस प्रतिशत का वृद्धि करना है। फिर ऑटो, रियल स्टेट, और क्षेत्र जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र है, के मामले में समायोजन किया जा सकता है। फिर पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि करने की बात आती है जो कि महत्वपूर्ण है। इस बजट से प्रत्येक उत्पाद के मामले में मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

एक बहुत ही युक्तिसंगत तर्क यह दिया जाता है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 60 प्रतिशत का हो गया है। इसलिए सेवा क्षेत्र के लिए सेवा कर का लगाया जाना एक उचित कदम है। भारत में हमारे पास जो जनस्वास्थ्य प्रणाली विद्यमान है, वह अभी भी अपर्याप्त है। अब हमारे यहां निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली शुरू की गयी है। कर्मचारी आमतौर पर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं और उनके स्वास्थ्य देखभाल पर सेवा कर लगा दिया जाता है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति यदि अपने अस्पताल के खर्चे का प्रत्यक्ष भुगतान करता है, तो उसे कोई भी सेवाकर नहीं देना पड़ता। स्वास्थ्य बीमा पर निर्भर व्यक्ति को पहले तो पॉलिसी पर सेवा कर का भुगतान करना पड़ता है और फिर अपने अस्पताल के बिल पर।

धनी लोग तो बड़े घरों में रहते हैं। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करने वाले लोग अब छोटे–छोटे अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। स्थानीय आवास बोर्ड आंतरिक और बाहरी तौर पर विकास शुल्क वसूलते हैं। अतः मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना अधिक महंगा हो जाता है।

अल्प लागत वाली विमान सेवाएं लाभ में चल रही हैं जब कि लग्जरी एयरलाइंस घाटे का सौदा हो चुकी हैं। इसलिए भारत में पर्यटन बढ़ाने के लिए, अल्पलागत वाली विमान सेवाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि अब पूरे विश्वभर में अल्पलागत वाले विमान सेवाओं का चलन हो गया है। लेकिन हमारे यहां सभी प्रकार के विमान यात्रियों से दस प्रतिशत अधिक किराया लिया जा रहा है। इस वर्ष से अब हमने विभिन्न प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाओं का दायरा बढ़ा दिया गया है। अतः कुछ सूचना को डाउनलोड करने हेतु किए जाने वाले भुगतान को भी अब सेवाकर के दायरे में लिया गया है।

सरकार शिक्षा के अधिकार की बात करती हैं। हमारे यहां बड़ी संख्या में कोचिंग केन्द्र और वाणिज्यिक प्रशिक्षण केन्द्र मौजूद हैं। प्रत्येक को कर के दायरे में लिया गया है जिससे शिक्षा अधिक महंगी हो गयी है। इस देश में न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि वाणिज्यिक परिसर को किराए पर देने पर सेवाकर लिया जाना चाहिए लेकिन आवासीय परिसर को किराये पर देने पर कोई सेवाकर नहीं लिया जाना चाहिए। अब वर्ष 2010 से किसी भी प्रकार के परिसर को किराए पर देने पर सेवा कर देना पड़ेगा। गत तीन वर्षों से प्रत्येक चीज पर सेवाकर लगाया जा रहा है। इससे मुद्रास्फीति की पूरी प्रक्रिया में और वृद्धि होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति की इस पूरी प्रक्रिया में सुधार किया जा सकेगा। तेल के मूल्य बढ़ने के कारण होने वाले प्रभाव से स्थिति और भी बिगडेगी।

कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है। विशेषकर हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ पा रही है और फिर वैश्विक मुद्रास्फीति के प्रभाव

को भारत में आयात किया जा रहा है। हमें इस बारे में गंभीर रूप से विचार करना चाहिए और कुछ साहसिक उपाय करने चाहिए। इसलिए, हमें एक बड़ी नीतिगत पहल करने की जरूरत है। हमें अपने कृषि क्षेत्र को बचाने की जरूरत है, उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है और निजी क्षेत्र के निवेश की जरूरत है। चीनी के बारे में यह कहा गया है कि इसका स्वरूप मौसमी होने के अलावा इसके उत्पादन में भी कमी आने के कारण इस वर्ष इसके मूल्य काफी बढ़े हैं। मैंने इस संबंध में आंकड़े की जांच करने की कोशिश की और यह पाया कि अक्तूबर 2009 से 10 मार्च 2010 तक हमने अधिक मात्रा में इसका आयात किया और चूंकि वैश्विक स्तर पर इसके मूल्य काफी अधिक थे, हमने चीनी के मूल्य के साथ ही मुद्रास्फीति का भी आयात कर लिया।

राजस्व घाटा जो कि तीन वर्षों के रोडमैप में दर्शाये गये हैं, कतिपय धारणाओं पर आधारित हैं। पहली धारणा तो यह बनाई गयी है कि अगले वर्ष विनिवेश से लगभग चालीस हजार करोड़ रूपये की प्राप्ति होगी। लेकिन यह थोड़ा जोखिमकारी प्रतीत हो रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार का विनिवेश के मामले में दृष्टिकोण कुछ अलग प्रकार का रहा है। अनुभव यह रहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर प्रबंधन में परिवर्तन किए बिना ही बाजार में डाल दिये गये ओर वास्तविक तौर पर हम केवल खरीददार ही ढूंढ पाये, बाजार में वास्तविक विनेश करने वाले नहीं। यूनिट 64 का मूल्य स्टाक एक्सचेंज घोटाले के बाद घट गया और शेयरों के मूल्य काफी नीचे आ गये। हमारी दूसरी कठिनाई 3–जी स्पेक्ट्रम की बिक्री से प्राप्त होने वाले अनुमानित 35000 करोड़ रूपयों को लेकर है। भारत में वर्ष 2001 और 2007 के बीच दूर संचार बाजार और इसके लाभ में काफी वृद्धि हुई थी। अतः लोगों ने 2–जी स्पेक्ट्रम के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर 1651 करोड़ रूपये का भुगतान किया। बाजार मूल्य की तुलना में 7000 करोड़ रूपये का मूल्य प्राप्त हुए थे।

मैंने कराधान की उच्च दरों का उल्लेख किया था, जिनका कि उपबंध किया गया है, सेवा कर का जिस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य रेलवे भाड़ा, संपत्ति तक विस्तार किया गया है, जिससे कि जीवन की आवश्यक वस्तुएं और भी महंगी हो गई हैं। मैंने देश में वर्तमान खाद्य संकट का भी उल्लेख किया था, जिसमें कि न केवल हमारे यहां खाद्यान्नों की कमी हो रही है, हमारी उत्पादकता बढ़ नहीं रही है और हमारी कीमतें बढ़ रही हैं। मैंने 40000 करोड़ रूपये की विनिवेश आया की मान्यता पर विचार किया था। नौ पार्टियों को 2–जी स्पैक्ट्रम आवंटित किया गया है। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स, जिन्हें कि 2–जी आवंटन से बाहर रखा गया है, वे 3–जी स्पैक्ट्रम के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे।

यदि हमें एक विशिष्ट स्तर पर व्यय करना है, विकास दर को बनाये रखने के लिए, आठ से नौ प्रतिशत की विकास दर को छूने के लिए इस प्रकार का व्यय आवश्यक है। 2008–09 के लिए पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में व्यय 24.56 प्रतिशत बढ़ गया। यदि हमारा व्यय 24 प्रशित तक बढ़ रहा है तो अगले वर्ष यह पूर्वानुमान करना कि यह घट जाएगा, यह केवल आठ प्रतिशत बढ़ेगा, जबकि आप अगले वर्ष का पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अधिक विकास दर वाले वर्ष के रूप में पूर्वानुमान करते हैं, इस संख्या पर पुनः गौर करने की आवश्यकता होगी। सरकार के वित्तीय लेखों में कतिपय मदें हैं जोकि बजट में स्वयं को नहीं दर्शाती।

हालांकि इन्हें सरकारी लेखाओं में नहीं दर्शाया जाता है, जहां तक वित्तीय घाटे का संबंध है इन्हें दर्शाया नहीं जा रहा है। हाल ही के सीएजी प्रतिवेदना में से एक में इससे मिलता–जुलता वक्तव्य है कि वित्तीय लेखाओं और बजट दस्तावेजों में पूर्ण विसंगति है। यह आवश्यक है कि अवसंरचना में सार्वजनिक निजी साझेदारी शामिल हो, काफी बड़ी मात्रा में सरकारी खर्च शामिल हो और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अवसंरचना प्रगति और विकास में वृद्धि करनी होगी। हमारे देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना में समस्याएं मौजूद थी। स्पष्टतया चीजों को रातों रात नहीं बदला जा सकता। अतः वे परियोजनाएं जो लंबित पड़ी हैं, उनके नये टेंडरों को देने में कुछ समय लगेगा।

हमने अब राजमार्गों को बनाने में स्वदेशी क्षमता विकसित कर ली है। प्रत्यक्ष कर कोड में अी भी काफी बहस की आवश्यकता है। हमने माननीय वित्त मंत्री जी को भी कुछ सुझाव दिए हैं। यह वर्ष ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। अगले वर्ष जबकि प्रत्यक्ष कर कोड पूर्णतः कार्यान्वित किया जाता है और प्रत्यक्ष कर कोड में मूल प्रस्ताव एक संकेत हो, तो यह बहुत आकर्षक लगेगा। तब इसके साथ कतिपय जोखिमपूर्ण परिस्थितियां आ जाएंगी। निश्चय ही यह वर्ष सौभाग्यवश उस अर्थ में राहत वर्ष है कि इस वर्ष उन छूटों को हटाया नहीं गया है।

इस स्लैब में बड़ी संख्या में लोग जो कि राहत पाएंगे, वे सभी कर्मचारी हैं, उन्हें वह लाभ नही मिलेगा जो कि आपकी बड़ी संख्या ने उन्हें दिया है। पिछले वर्ष बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि 'एक रैंक एक पेंशन' के बोर में काफी आकांक्षा थी और पूरे देश में ऐसी धारणा बन गयी कि भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में 'एक रैंक एक पेंशन' वास्तव में दी जा रही है। हम यह सुस्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहेंगे क्योंकि कार्यान्वयन बजट यह दर्शा रहा है कि इसे किया नहीं गया है। विश्व की आबादी का 11 प्रतिशत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना आजीविका पर्यटन से प्राप्त करता है। हमारे यहां धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन मौजूद हैं। अतः हमें इन क्षेत्रों के बारे में कुछ पहलों को करने की आवश्यकता है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय में निधियों का उपयोग उपयुक्त रूप से नही किया गया है। बजट में कुछ निराशाजनक प्रवृत्तियां हैं। सरकार का आंतरिक घाटा 2008–09 में 23,74,743 करोड़ रूपये से बढ़कर 35,55057 करोड़ रुपये हो गया है, जिसे अब 3700,000 करोड़ रूपये हो गया है। यदि हमारे बाह्य और आंतरिक ऋणों को जोड़ दें तो यह 38,04180 करोड़ रूपये हो जाएगा। जिसे हमारे जनसंख्या से भाग देने पर प्रत्येक भातीय हमारे सार्वजनिक ऋण के कारण 33,966 रूपये तक ऋणग्रस्त हैं। अतः हमारे संसाध्नों या राजस्व एकत्रण के प्रबंधन में अत्यंत बुद्धिमता और कुशलता की आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि भारती अर्थव्यवस्था विकास करेगी। परन्तु इसका विकास मुद्रास्फीति के साथ होगा, और यह विकास

इस बजट के कारण नहीं होगा, परन्तु यह विकास भारत में जो हमारी उद्यमशीलता है उद्यमशीलता के कारण होगा, जहां कि सेवा क्षेत्र जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 60 प्रतिशत तक हैं जो कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में और अधिक गति से बढ़ रहा है।

प्रभात झा

महोदय, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं श्री सी0 रंगराजन, उन्होंने प्रधान मंत्री जी को जो रिपोर्ट 18 फरवरी, 2010 को सब्मिट की है, उसके कुछ अंश मैं आपको सुना रहा हूं, जिनसे इस बजट की पोल खुलती है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है 'यूपीए सरकार का राजकोषीय घाटा चरमराने के कगार पर है। बीते दो साल में जिस अंदाज से सरकार ने राजकोषीय प्रबंधन किया है, उसकी वजह से राजकोषीय घाटा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है।' यह मैं नहीं कह रहा, यह प्रधान मंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं। अभी राजीव जी कह रहे थे कि महंगाई कम होगी, जबकि श्री सी0 रंगराजन जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 'सरकार के खराब' प्रबंधन के कारण देश में महंगाई बढ़ी है।' उन्होंने यहां तक कहा है कि 'यदि खाद्य पदार्थों की कीमतों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो उसकी आग अन्य क्षेत्रों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी।' उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि 'अगले वित्त वर्ष में भी महंगाई से कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।' माननीय (राजीव) शुक्लजी ने कहा कि एक महीने में करामात देखिए, जबकि प्रधानमंत्री जी के सलाहकार, श्री सी. रंगराजन कह रहे हैं कि दो साल तक अभी कोई उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट में साफतौर पर सरकार को कहा गया है कि 'चावल के स्टॉक की स्थिति अच्छी नहीं है। कृषि और बिजली दोनों ही बेहद संक्रमण काल से गुजर रहे हैं।'' अब मैं श्री प्रणब मुखर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि श्री सी. रंगराजन की रिपोर्ट को सही मानूं या आपके बजट में आपने जो आर्थिक व्यवस्था की प्रशंसा की है, उसको सही मानूं?

आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक समय भारत 88 हजार करोड़ कर्ज की ब्याज की अदायगी करता था, आज 3 लाख करोड़ से अधिक हम सिर्फ ब्याज दे रहे हैं। टोटल बजट का 20–25 फीसदी हम ब्याज पर खर्च कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो हमने दिखाया है, उसमें प्रणब दादा ने कहा है कि 29 प्रतिशत, जो वे बातें कर रहे हैं कि हम इतना काम करेंगे, कर्ज़ वे और लेंगे और उसके बाद उस काम को वे करेंगे। प्रस्तुत बजट 2010–11 में कहीं कोई चीज नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देकर पूछना चाहता हूं कि अगर आपका पिछला बजट बहुत अच्छा था तो 20 रुपए, एक थाली और एक रुमाल के लिए प्रताप गढ़ में 63 लोगों की मौत क्यों होती और 20 रूपए और थाली के लिए लोग क्यों दौड़ते? आपके बजट ने गरीबी दी है, आपके बजट ने लोगों की जान ली है। अभी आप कह रहे थे कि विकास दर बहुत बढ़ रही है। आपका विकास आपकी सरकार को मुबारक। मेरे देश की हालत क्या है, इसे आपकी रिपोर्ट बताती है। नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट है कि लगभग 70 फीसदी जनता 20 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करती है। जो विकास दर जिन्दगी के बजाए मौत दे, जो विकास दर रोटी के बदले लात दे, जो विकास दर हमारी गरीबी से खिलवाड़ करे, आपकी ऐसी विकास दर को लेकर हम क्या करेंगे? हमें आपकी यह विकास दर नहीं चाहिए।

हमें चाहिए रोज़ी, हमें चाहिए रोटी, हमें चाहिए कपड़ा, हमें चाहिए मकान। आज भी आपका यह बजट हमें ये सब चीजें देने में असमर्थ है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारी 70 फीसदी जनता, जो रोज़ 20 रुपए कमाती है, उसके लिए आपके इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है, आपको इस बारे में बताना चाहिए। आपकी सरकार की तीन रिपोर्टें आती हैं – सबसे पहले तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई। वह कहती है कि हमारे देश में 38 फीसदी गरीबी है। फिर एन.सी. सक्सेना साहब की रिपोर्ट आती है, वह कहती है कि इस देश की आधी जनता गरीबी की रेखा के नीचे है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है और वह कहती है कि 42 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनमें से सही आंकड़ा कौन सा है, यह आपको बताना चाहिए। देश में इतनी बड़ी भुखमरी है, गरीबी है, बेबसी है और इनको दूर करने के लिए आप इस बजट में क्या दे रहे हैं? इन गरीबों के लिए क्या है – खून के आंसू, आंकड़ों की जुगाली? आखिर आप इनको क्या देना चाहते हैं – 'मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन वर्गों के लिए इस बजट में क्या रखा है?

आपने चुनाव के समय वोट लेने के लिए कहा कि हम 3 रुपए किलो पर गेहूं, चावल, सब कुछ देंगे, लेकिन आपने क्या किया? लगभग एक साल पूरा होने जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने 3 रूपए प्रति किलो गेहूं या चावल दिया? चुनावी करके आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत सकते।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यहां कांग्रेस का घोषणा–पत्र लाया हूं। इस घोषणा–पत्र के पृष्ठ 15 पर कहा गया है कि– ''भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, खाद्य सुरक्षा को अधिकार बनाने संबंधी कानून पारित करेगी, जिसके अंतर्गत सब लोगों को, खासकर समाज के कमज़ोर तबके के लोगों को पर्याप्त भोजन देने की गारंटी होगी। शहर या गांव में, कहीं भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हरेक परिवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कानूनन 25 किलो चावल या गेहूं, 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह उपलब्ध कराएगी'। प्रणब जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतने माह बीत गए हैं, क्या आपने इसे उपलब्ध करा दिया है? आप ये वायदे क्यों करते हैं? आपके घोषणा–पत्र में किए गए वायदों को आपको निभाना चाहिए और यदि आप नहीं निभाते हैं, तो जनता आपको नहीं छोड़ेगी, आप कुछ भी करिए, जनता आपको नहीं छोड़ेगी।

उस समय आपको वोट लेने थे, इसलिए आपने किसानों

के 72,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ कर दिए। हम नहीं जानते कि किसानों का कर्ज़ा माफ हुआ या नहीं हुआ। इस पर आपको श्वेत–पत्र जारी करना चाहिए। आपके ही कृषि राज्य मंत्री सदन में एक सवाल के उत्तर में कहते हैं कि 2009–10 के दौरान महाराष्ट्र के 28 जिलों में 463 किसानों ने आत्महत्या की। यह कैसा कर्ज़ा आपने माफ किया है, यह कैसी राहत आपने दी है? आप कह रहे हैं कि हमने किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज़ा माफ किया है। आप वोट लेते समय राहत का पैकेज देते हो और जब वोट मिल जाता है, तो उन्हें भूल जाते हो। मुझे मालूम है कि 2013 में आप फिर से यही करेंगे, यही जो आपने 2008–09 के बीच किया है। जनता को का यह सिलसिला बंद होना चाहिए। बजट के नाम पर आपके जो 189 बिन्दु हैं, उनमें कहीं जनता के हित की बात नहीं है। इस पर आपके कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि 373 जिले सूखे की चपेट में हैं और आप किसानों के लिए केवल 400 करोड़ रूपए दे रहे हैं, यानी एक जिले को, एक करोड़ रूपया भी नहीं मिल रहा है। यह कैसा बजट है आपका? आप किसके साथ न्याय कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष जी, अभी राजीव शुक्ल जी कह रहे थे कि दलहन और तिलहन के लिए 60,000 गांव बनाए जाएंगे। इंदिरा जी भी यह बात कहती थीं, उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया। यह वर्षा घोषित क्षेत्र में दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि 60,000 गांवों के लिए मात्र 300 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आप हिसाब लगा लीजिए कि एक गांव को 50,000 रुपए तक नहीं मिल रहे हैं। आज की तारीख में 50,000 रूपयों में एक कुंआ तक नहीं खोदा जा सकता। यह आंकड़ों का हिसाब किसको दे रहे हैं? इस पर आप कौटिल्य का उदाहरण दे रहे हैं। आपने अपने भाषण में कौटिल्य की चर्चा करते हुए कहा कि – 'लोक संपन्नता, प्रचुर उत्पादकता और अन्य बातों के साथ–साथ वाणिज्यिक समृद्धि और वित्तीय संपन्नता निर्भर करती है ....', लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में कृषि उत्पादकता को नकारात्मक दर पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे बताइए कि इसके लिए जवाबदेह कौन है – विपक्ष या आपका सत्ता पक्ष?

अब मैं 'जय जवान' पर आता हूँ। आपने जवानों के साथ क्या किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर हम जानते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं, एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुंआ है, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है। उसके बावजूद आपने कितनी वृद्धि की है, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कितने हजार करोड़ रुपए की वृद्धि की है? आपने लगभग पांच हजार करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। दुनिया की क्या हालत है? अमेरिका ने दस बिलियन डॉलर पाकिस्तान को सिर्फ दिया है ओर वह आपके खिलाफ दस बिलियन डॉलर का हथियार खरीद रहा है। अमेरिका जो सामान सप्लाई करता है, वह 695 बिलियन डॉलर का है, उसके आगे अगर आप जर्मनी, फ्रांस आदि सबको देखेंगे, तो ये सब आगे जा रहे हैं और हम कितनी वृद्धि करते हैं? हमारी सेना आपके टोटल बजट का तीन फीसदी मांगती है और आप डेढ़ या दो फीसदी देते हैं। इससे कैसे काम चलेगा। आपको पूरा आधुनिकीकरण करना है, आप वहां पर जाकर कैसे लड़ेंगे और इन सारी चीजों को देखने के बाद भी आपको इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, लेकिन आप उतनी बढ़ोतरी नहीं करते हैं। वहीं भारत का रक्षा व्यय, सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत है और यह हमारी रक्षा आवश्यकताओं की दृष्टि में अपर्याप्त है। हमारी सेनाओं ने इसे बढ़ाकर जीडीपी का तीन फीसदी करने की मांग की है, लेकिन हम यह नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप थोड़ा सा नाराज भी होंगे, ये जो बजट के 189 बिन्दु हैं, इन बिन्दुओं में युवा नाम का शब्द, बेरोजगारी नाम का शब्द नहीं है। माननीय कांग्रेस के महामंत्री युवा गांव–गांव जाते हैं, अगर वह किसी चापाकल पर नहाते हैं, तो पूरे देश में फुसुर–फुसुर होने लगता है कि चापाकल पर नहाया। अरे भाई, आपने तो एक दिन नहाया, लेकिन देश की जनता तो चापाकल पर रोज नहाती है। आपने चापाकल का पानी पी लिया, तो बड़ा भारी काम कर दिया।

युवराज का भी ध्यान प्रणब जी ने नहीं रखा है। इस पूरे बजट में युवा के नाम पर एक शब्द नहीं है। मेरी यह चुनौती है कि अगर आपने युवाओं और बेरोजगारों के नाम पर कुछ भी लिखा हो, तो मैं यह सदन छोड़ने को तैयार हूँ। उनके बारे में एक चीज नहीं है। आपके युवराज, आप इन्हें महाराज, सबकुछ कहिए, लेकिन देश का युवा आपसे पूछ रहा है कि आपने उसको इस बजट में क्या दिया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपने उन्हें सिर्फ ठेंगा दिखाया है। यह कैसी है? क्या इसे से आप बच जाएंगे? क्या आप संभल जाएंगे?

आप राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रेमी बनते हैं, लेकिन आपने उसके बजट में दो करोड़ की कटौती कर दी। पिछले साल आपने बजट में 36.22 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन अब आपने उसको 34.17 करोड़ कर दिया है। आप कह रहे थे कि ''भारत निर्माण'' करेंगे, कैसा भारत निर्माण? आपके ही मंत्री जी कहते हैं, जो आपका ग्रामीण योजना का सबसे बड़ा दावा है और बजट अनुमान की तुलना में 2009–10 में 45 प्रतिशत अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव करते हुए आपने खुद ही कहा है, लेकिन वित्त मंत्री महोदय के इस दावे की पोल स्वयं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने खोलकर रख दी। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क यामजना के तहत वर्ष 2009–10 में कुल 24,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराना था, लेकिन अब तक केवल 10,262 किलोमीटर सड़क बनी है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह आपके मंत्री जी की रिपोर्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि कैसा भारत निर्माण? किस तरह का भारत निर्माण? आपसे किसान दुखी है, आपसे देश का युवा दुखी है, आपसे देश की महिला दुखी है, आपसे इस देश का गरीब से गरीब तबका दुखी है और गांव के गांव पलायन कर रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है।

महोदय, मैं यहां पर राजनीतिक विद्वेष से नहीं खड़ा हूं, मैं भारत की पीड़ा लेकर खड़ा हूं और भारत की पीड़ा को व्यक्त करने का अधिकार मुझे है, इसलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूं। आपका बजट एक परंपरा का निर्वाह हो सकता है, लेकिन मेरे भारत को एक ऐसा बजट चाहिए, जिससे हर खेत को पानी मिले, हर पेट को रोटी मिले और हर सिर को छत मिले, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद। ■

लोकसभा

यशवंत सिन्हा

श्री यशवंत सिन्हा ने चर्चा आरंभ करते हुए कहाः बजट भाषण में तीन मुख्य चुनौतियों का जिक्र किया गया है। हमारे सामने पहली चुनौती 9 प्रतिशत की दर को और इसके बाद दोहरे अंकों वाली वृद्धि दर को प्राप्त करने की है। दूसरी चुनौती विकास को और अधिक समावेशी बनाने की है और तीसरी चुनौती सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्ग के अवरोधों को हटाने की है। बजट भाषण में उल्लेखित तीन चुनौतियों में महंगाई की चुनौती का जिक्र सरकार ने नहीं किया है। इकानॉमिक सर्वे कहता है कि एक्सेसिव हाइप होने की वजह से इन्फलेशनरी एक्स्पेक्टेशन्स बढ़े और इन्फलेशनरी एक्स्टपेक्टेशन्स बढ़ने के चलते लोगों ने होर्डिंग किए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए सीधे सरकार जिम्मेदार है। हमें ग्रीन शूट्स इकानॉमी नजर आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम उत्सव मनाने लगे और कहने लगे कि सारे संकट पार कर लिए। हमने इस पर काबू पर लिया और अब हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्सव मनाना जल्दबाजी होगी। सारे अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि 7.2 परसैंट ग्रोथ रेट इस साल अचीव करने के लिए हमें लास्ट क्वार्टर में, जनवरी–मार्च क्वार्टर में लगभग 9 प्रतिशत विकास दर को हासिल करना पड़ेगा। विकास दर कोई खाता नहीं है। आप आंकड़ों के मायाजाल में फंसाइए कि हम यहां ले गए, वहां ले गए। गांव के गरीब को इससे संतोष नहीं होता है। महंगाई की चुनौती और कृषि के संकट को इतना महत्व नहीं दिया गया है कि जितना महत्व इस बजट में दिया जाना चाहिए था। वित्त मंत्री के जो आंकड़े हैं अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रोथ और इंफ्लेशन के टर्म्स में कहां तक सही साबित होंगे, इस पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है। वित्त मंत्री जी इस बात को कहीं न कहीं गौण कर गए कि उसी 13वें वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि रेवेन्यू डैफिसिट 4 परसैंट होना चाहिए जो आपने अधिक दिखाया है। बजट के जो अनुमान हैं जो आंकड़े हैं उस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता है और उसे एचीव करना बहुत मुश्किल होगा। राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा क्योंकि खर्च में वृद्धि को अत्यंत कम करके दिखाया गया है और आमदनी में वृद्धि का अनुमान 18.5 प्रतिशत से अधिक का है जो पिछले दस साल में से केवल दो वर्षों में संभव हो पाया है जबकि आर्थिक विकास की दर 9 प्रतिशत से अधिक रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में 49 प्रतिशत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के मामले पर सरकार को अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए। पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टैच्युटरी बैंकिंग होना बहुत जरूरी है। जो पेंशन फंड अथॉरिटी है, वह बिना किसी कानून के, बैंकिंग से चल रही है और 1 जनवरी, 2004 से सारे सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जो पेंशन का पैसा जमा हो रहा है, उसे मैनेज करने का काम वह अथॉरिटी कर रही है, लेकिन सब कुछ नॉन स्टैच्युटरी बेसिस पर है। मैं जानना चाहता हूं कि आज के दिन इस पर आपका स्टैंड क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की क्या भूमिका होगी इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कोड को 1 अप्रैल, 2011 से लागू करने के लिए भरसक प्रयास करने होंगे और अगर इसमें गति नहीं दिखायी दी तो शायद 1 अप्रैल, 2011 को भी हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। हमें जहां एक ओर इस बात की चिंता है कि इनफ्लेशन आम आदमी को पीस रहा है। परंतु सरकार इस संबंध में, दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रही है और अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपने जो 26 हजार करोड़ रुपये डायरेट टैक्सिज में कम दिखाया है, सैक्रीफाइस किया, वह किसके लिए किया, जो इस मुल्क में तीन लाख से आठ लाख रुपये तक सालाना कमाते हैं। तीन लाख रुपये सालाना का मतलब हुआ, 25 से 70 हजार रुपये प्रति माह जो कमाता है, उसको आपने छूट दी है और साल भर में 50 हजार रुपये की छूट आठ लाख तक की आमदनी वालों को हो जाएगी। अपने कहा है–यह आम आदमी का बजट है। आम आदमी की परिभाषा क्या है? यूपीए की परिभाषा में शायद जो 25 हजार से ज्यादा कमाता है, वह आम आदमी है इसलिए उसको छूट दो और जो एक दिन में 25 रुपये कमाता है, उसको लूट लो। मैं महंगाई का जिक्र इसलिए कर रहा था कि महंगाई की समस्या को वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में एक महत्वपूर्ण समस्या मानी होती तो उसके उपाय भी होते। लेकिन यहां तो उलटा ही हुआ। तीन कदम इन्होंने अपने बजट में ऐसे उठाए हैं, जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी। बड़ी चर्चा हो रही थी कि स्टिमुलस पैकेज वापस होगा या नहीं? स्टिमुलस के तहत इन्होंने सैन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था। सब लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि मंत्री जी उसको बढ़ाएंगे। इन्होंने उसे दो प्रतिशत बढ़ाया। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब इन्होंने कम किया था, तो उस कमी से क्या महंगाई कम हो गयी थी? लेकिन कीमत घटी नहीं। जब इन्होंने पांच प्रतिशत आयात शुल्क पेट्रोल क्रूड पर कम किया था, तो कीमत नीचे नहीं आई थी, लेकिन जब इन्होंने दो प्रतिशत बढ़ाया था और उन्होंने पांच प्रतिशत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात शुल्क बढ़ाया, एक रुपया डीजल और एक रुपया पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया तो उससे बाजार में आग लग गई। उसके बाद सर्विस टैक्स के दायरे में रियल एस्टेट को ले आए। यदि कोई अपना फ्लैट खरीद रहा है और किश्त में पैमेन्ट कर रहा है तो उसको 10.33 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होगा, जो कि उसकी कीमत को और बढ़ाएगा। सीमेंट और स्टील की कीमत 12 रुपए प्रति बैग बढ़ गई। फर्टिलाइज़र की कीमत के बारे में इन्होने स्वयं ही कहा है कि इसे भी हम एक अप्रैल से बढ़ाएंगे। इन्हीं के

मिनिस्टर ने कहा है कि मैं इसका विरोध करता हूं। ये जो फर्टिलाइज़र की, यूरिया की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूं और करता रहूंगा। कोल के ऊपर ग्रीन फंड बनाया, आप बनाइए, लेकिन ग्रीन फंड में आपने कोयले पर शुल्क लगा दिया, उससे तीन हजार करोड़ रुपए आएंगे। सर्विस टैक्स रेलवे के ऊपर डाल दिया। इसके चलते इंटरमीडिएट ग्रुप्स के ऊपर उसमें प्राइसेस में वृद्धि होगी और अगर इसमें वृद्धि होगी तो सब चीजों में वृद्धि होगी। कोयले की कीमत बढ़ गई, क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी महंगी है।

मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी जब सदन में जवाब दें तो जरूर इस बात को कहें कि हम कमोडिटी एक्सचेंजेस में व्हीट फॉरवर्ड ट्रेडिंग के ऊपर जल्दी ही रोक लगाने जा रहे हैं। इन्होंने अपने खर्चो में बेइन्तिहा वृद्धि की उसके बाद इसके भाग्य से क्या हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। इनके जितने एक्सैसेस थे उन्हें इन्होंने वैश्विक वित्तीय संकट की आड़ में छिपाने का प्रयास किया। वह एक ढाल बन गया। अब चुनाव खत्म हो गए तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी को फिस्कल डिसीप्लिन याद आ रहा है। हम तो चुनाव जीत गए। अब उस जनता को रगड़ो जिसने हमें जिताया हैं जब अंतिम साल के पहले वाला साल आएगा तब फिर खजाना खोल देंगे। जिस ग्रोथ रेट पर आप गर्व मना रहे हैं वह कंजम्पशन लेड ग्रोथ है। कागजों पर विद्युतीकरण हो गया। इन्होंने कहा, किसानों को ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइज दिया, इससे कीमतें बढ़ीं। वर्ष 2004–05 में जब ये आए थे, तब व्हीट का एमएसपी 640 रुपए था, इन्होंने 10 रुपए बढ़ाया और यह 650 रुपए हो गया। उसके बाद वर्ष 2007–08 आया, उसमें अचानक यह जंप करके 1,000 रुपए चला गया, क्यों? क्योंकि चुनाव थे। वर्ष 2008–09 में 80 रुपए बढ़ा, वर्ष 2009–10 में 20 रुपए बढ़ा। आप व्हीट को देखें, पैडी को देखें, कोर्स ग्रेन्स को देखें, आप यहा भी पाएंगे कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाया। चुनाव समाप्त हो गया, उसे फिर कम्प्रेस कर दिया। इनका मतलब निकल गया। जब बजट में आधारभूत ढांचे के लिए 1,73,552 करोड़ रुपए की राशि रखी गयी तो हम लोग बड़े खुश हुए। मैं देख रहा था कि सड़कों के लिए 2,400 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं और रेलवे के लिए महज 950 करोड़ रुपए की बढोत्तरी की गयी है। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में जो इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड है, यह एक लाख करोड़ रुपए की स्कीम्स को सपोर्ट करेगी।

इस साल वह कह रहे हैं कि कुल निर्गत राशि मार्च तक मात्र 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। वह एक लाख करोड़ रुपए घटकर नौ हजार करोड़ रुपए मार्च के अंत तक हो जाएगा। टेक–आउट फाइनेंसिंग का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। अभी नियम बन रहे हैं। चाहे वह कृषि हो, एनर्जी हो, इरीगेशन हो, इन्वायर्नमेंट–क्लाइमेट चेंज हो, हर जगह इन्होंने प्रसाद की तरह तीन सौ करोड़, दो सौ करोड़ और एक सौ करोड़ रुपए बांटे। इससे कहीं कोई तरक्की होने वाली नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वित्त मंत्री जी हाउसिंग के लिए इनकम टैक्स में जो छूट है, जिसे तीन वर्षो में 15 हजार रुपये सालाना से मैं डेढ़ लाख रुपये सालाना कर देता। इस एक कदम के द्वारा मैंने यह सुनिश्चित कर दिया था कि फ्लैट खरीदने वाले किसी नागरिक को 10 लाख रुपए तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के बावजूद पिछले आठ सालों से एक लाख पचास हजार पर स्थिर है। उसे बढ़ाने की जरूरत थी। दूसरा बिन्दु जो मैं रखना चाहता था और शायद वह मेरा अंतिम बिन्दु होगा, वह यह है कि हम सब ने इस बात पर बहुत गर्व किया कि हमारा डोमैस्टिक सेविंग्स रेट बढ़ते–बढ़ते ईस्ट एशियन कंट्रीज के लैवल पर चला गया। 37 प्रतिशत, 38 प्रतिशत और आपकी इन्वैस्टमैंट की जो दर थी, वह भी बढ़ी। यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण पर एक नजर डालें तो पायेंगे कि घरेलू बचत की दर में तेजी से गिरावट आयी है और एक वर्ष में 390 बेसिस प्वाइंट गिर गयी है। जो सरकार में घाटे को परिलक्षित करती है। यह लॉग टर्म डैमेज इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है। इस देश में बचत करने की जो परम्परा है, उससे यह देश चलता है। विदेशों की ताकत पर यह देश नहीं चलता है। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में बोलते हुए रेट बढ़ाने की बात कही, तो हम लोग सुनते रहे। लेकिन जब यह असहनीय होने लगा तो सदन से वाक–आउट कर गए।

मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि ठीक 26 फरवरी, जिस दिन प्रणव बाबू ने यहां पर बजट पेश किया, उसके दो दिन पहले गुजरात का बजट पेश हुआ था और गुजरात के बजट में पूरी कांग्रेस पार्टी वाक–आउट कर गयी थी, तो अहमदाबाद के लिए वह ठीक है और दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। मैं किसी कंपनी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत लोगों को बहुत मुश्किल हो जायेगी। मेरा यह कहना है कि इसमें वित्त मंत्री जी ने जो दावे किये हैं, वे दावे सही नहीं है। मेरा कहना यह है कि उन्होंने एक तरफ आम आदमी को मारा है और दूसरी तरफ जो धनी हैं, सम्पन्न हैं, उनको और धनी बनाया है, सम्पन्न बनाया है। ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का इंजन धकधक करते हुए आगे बढ़ जाएगा तो मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा, वित्त मंत्री जी आपके अनुमान गलत हैं। इस बजट से आम लोगों की दशा और खराब होगी। अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा और बजट में आपने जो आंकड़ेबाजी दिखायी है वह सही सिद्ध नहीं होगी। इसलिए हम लोग इस बजट का विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह बजट आम आदमी का नहीं है।

निशिकांत दुबे

मैं जिस पिछड़े राज्य झारखण्ड से आता हूं , उसकी जिस तरह से उपेक्षा हुई है, इस्टर्न इंडिया की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, युवाओं की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, पिछड़ो की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, आम आदमी की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। यह बजट पिछड़े क्षेत्र, विद्यार्थियों और युवाओं का विरोधी है तथा इसमें पारदर्शिता नहीं है। बजट में सेटलमेंट कमीशन के पास स्वीकार होने वाले मामलों का दायरा बढ़ाया गया है। जबकि केसज़ पेंडिंग फॉर एसेसमेंट

का निर्धारण एसेसमेंट ऑफिसर तय करता है न कि सेटलमेंट कमीशन। लेकिन अब इन मामलों का निर्धारण सेटलमेंट कमीशन करेगा जिसमें कृपापात्र अधिकारी नियुक्त होते हैं। कर प्रस्तावों में तीन लाख रुपए से आठ लाख रुपए तक आय वालों को 50,000 रुपए की छूट दी गयी है लेकिन एक लाख 60 हजार रुपये से लेकर तीन लाख रुपए तक की आय वाले एक करोड़ एसेसी को कुछ नहीं दिया गया। कारपोरेट सरचार्ज को घटाकर 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

इंडस्ट्रियलिस्ट्स को 2.5 प्रतिशत का फायदा देकर इसमें कौन–सी ट्रांसपेरेंसी नजर आती हे। मैट को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया। इससे कोई बड़ी कम्पनी प्रभावित नहीं होने वाली है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज और प्रिफ्रेंशियल लोकेशन चार्जेज पर टैक्स लगाया गया है इससे हाउसिंग सेक्टर प्रभावित होगा। बजट आने के बाद स्टील और सीमेंट के दामों में वृद्धि हुई है। यह कहा गया है कि स्पैक्ट्रम बेचकर 35,000 करोड़ रुपए सामाजिक क्षेत्र में लाए जायेंगे किंतु आज तक कोई स्पैक्ट्रम नहीं बेचा गया है। सरकार का कहना है कि नरेगा के अंतर्गत साढ़े चार करोड़ लोगों को 100 दिन का रोजगार देंगे। यदि मजदूरी 100 रुपये प्रतिदिन है तो इसके लिए न्यूनतम 45,000 करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन इसमें इसके लिए केवल 40,000 करोड़ रुपया रखा है। उसमें भी तीन प्रतिशत सर्विस चार्ज काटते हैं, तो इसका मतलब है कि इस योजना के लिए 37,000 करोड़ रुपया बचे। इस तरह से यह 8,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए का घाटा कहां से पूरा होगा?

बजट में एयर इंडिया के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि एयर इंडिया घाटा साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए का है। क्या इस राशि से एयर इंडिया का घाटा पूरा होगा? एयर इंडिया के बारे में एक श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए। गृह मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल दे रहे हैं। किंतु इस बजट में आई॰बी॰ के लिए 100 करोड़ रुपया घटा दिया गया तथा सी॰आर॰पी॰एफ॰ और बी॰एस॰एफ॰ के लिए भी पैसा घटा दिया गया है, केवल एन॰एस॰जी॰ के लिए पैसा बढ़ाया है। आई॰बी॰ का पैसा घटाकर एन॰आई॰ए॰ के लिए 15 करोड़ रुपया दिया है। इंडो–भूटान बार्डर तथा इंडो–बंगलादेश बार्डर के लिए पैसा घटा दिया गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट बैंकों की 11 हजार शाखाएं खोलने की घोषणा की है किंतु प्राइवेट बैंक, किसान, विद्यार्थी, छोटे दुकानदारों को एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बजट में स्किल डिवेलपमेंट पर बहुत खर्चा बढ़ाने तथा वर्ष 2022 तक 50 करोड़ कुशल कामगार तैयार करने की बात कही गयी है। किंतु इसके लिए केवल 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्या यह लक्ष्य पूरा होगा? सर्व शिक्षा अभियान में 80 प्रतिशत पैसा केवल टीचर की सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दे रहे हैं। पढ़ाई तथा आर॰एंड॰डी॰ के लिए एक भी फैसिलिटी क्रिएट नहीं की है। यह कहा गया है कि देश का विकास तब होगा जब देश में कोयला होगा।

कोयला पर 50 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। कोयला का ई–ऑक्शन हो रहा है लेकिन जब आप नोमिनेशन बेसिस पर कोयला देते थे ही तो ह 13 प्रतिशत फ्रीपावर देता था। 35 प्रतिशत पावर वह किस रेट पर बेचेगा, यह राज्य तय करता था। आज जब यह मार्केट यह तय करेगा तो देश में 15, 20, 25 रुपए प्रति यूनिट बिजली होगी। फिर कौन–सा आम आदमी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली ले सकेगा। बजट में त्रिपुर में एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट और गंगा–पदमा के लिए मुर्शिदाबाद में सैंट्रली स्पोंसर्ड लड मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात कही गयी है। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। भागलपुर और गोड्डा में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है। किंतु भागलपुर और भगैय्या में सिल्क क्लस्टर नहीं बन सकता, वहां मार्केटिंग की कोई सुविधा नहीं हो सकती। गंगा के कटाव के लिए साहबगंज जिले में कोई उपाय नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहां से कोई बड़ा नेता या मंत्री नहीं है। वित्त मंत्री ने बजट में बार–बार फिस्कल कन्सॉलिडेशन की बात कही गयी है। इसका मतलब है कि पहले जारी ऑयल बांड और फर्टिलाइजर बांड कहीं न कहीं करप्शन को जन्म दे रहे थे और कहीं न कहीं उसके मैनेजमेंट में परेशानी थी। सरकार खाद्य सुरक्षा की बात कर रही है किंतु खाद्यान्न इनफ्लेशन 17 प्रतिशत है। कृषि के लिए इस बार का आवंटन 2 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं किया, हरित क्रांति नहीं आयी, उत्पादन नहीं बढ़ा तो इस देश में कुछ नहीं होना है। पूरे देश को माइनर इरीगेशन के लिए 200 करोड़ रुपया, मेजर इरीगेशन के लिए 300 करोड़ रुपया और फ्लड मैनेजमेंट के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया है। बजट में कहा गया है कि 400 करोड़ रुपया पूर्वी राज्यों झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को दिया गया कि वहां हरित क्रांति होगी जबकि सोलर पावर के लिए 500 करोड़ रुपए केवल लद्दाख को दिए गए हैं। दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूरे देश को 300 करोड़ रुपया दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस बार 0.1 परसैन्ट राशि कम दी गयी है। पिछली बार यह जी॰डी॰पी॰ का 1.37 प्रतिशत था। किंतु इस बार 1.36 है। पूरे संथाल परगना में दो करोड़ आदिवासी, गरीब और दलित लोगों के लिए एक भी हॉस्पिटल नहीं है और आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ा दिया है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में शिक्षा के लिए जो पैसा केन्द्र दे रहा है उसका मात्र 50 से 60 प्रतिशत खर्चा हो रहा है। मिड–डे मील में बीस प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास में 25 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च 96 प्रतिशत ''नरेगा'' में हो रहा है। देश में 254 जिलों में पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। किंतु बजट में स्वच्छता के लिए पूरे देश के लिए 1200 करोड़ रुपए के लिए दिए गए हैं। इस बजट में शहरी विकास के लिए आवंटन में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है किंतु इस आवंटन का 80 प्रतिशत केवल सात राज्यों में बड़े शहरों में खर्च किया जा रहा है, छोटे शहरों का ध्यान नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2005–2006 और 2008–2009 में झारखंड के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का 50 प्रतिशत खर्च नहीं हो रहा है। सरकार को गरीब, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, शहरी विकास आदि किसी चीज की चिंता नहीं है। ये येन–केन–प्रकारेण सरकार में बने रहना चाहते हैं। ■

लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में ऐतिहासिक कदम : भाजपा

महिला आरक्षण विधेयक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में पारित हो गया। इसके साथ ही संसदीय प्रणाली में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता आसान हो गया। इस मुद्दे पर राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल (यू) के सांसदों ने हंगामा करते हुए विधेयक की प्रतियां फाड़ दी, जिसके चलते सात सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। विधेयक पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक है और भाजपा ने शुरू से ही इस विधेयक का साथ दिया। भाजपा सांसद श्रीमती माया सिंह ने कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने की बात 1994 में की थी। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को मौजूदा स्वरूप में ही पारित किया जाए, इसमें संशोधन बाद में किया जा सकता है। हम यहां भाजपा सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:

v#.k tVyh

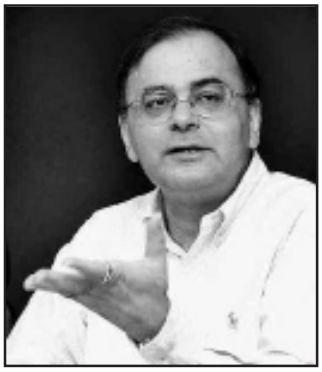

जो लोग सदन में उपस्थित है, उनके लिए यह बहुत बड़े सम्मान की बात है कि वे इतिहास के निर्माण के भागीदार बने हैं। हम सभी भारत के वर्तमान इतिहास के एक सर्वाधिक प्रगतिशील विधान के अधिनियमन का उपकरण बनते हुए ऐतिहासिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

तर्काधार

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के पीछे जो तर्काधार है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसा भ्रम है कि आरक्षण विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का सृजन करता है। सच्चाई यह है कि प्रकृति ने हम सबको समान रूप में पैदा किया है, संविधान ने भी हमको समानता प्रदान की है, किंतु समाज के कतिपय मतिभ्रंश ने कुछ समानों को असमान बना दिया है।

अतः आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई है, जिसके पीछे आशय यह है कि असमानता के यथार्थ को समानता की दृष्टि से संवारा जाए। जिनको असमान बना दिया गया है वे आज निर्णय लेने के समान भागीदार बनेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा एक ऐसा आवश्यक उपकरण बन जाता है, जो समानता की प्रक्रिया को धमाकेदार शुरूआत देता है। महिलाओं का समाज में 50 प्रतिशत स्थान है। गत 63 वर्षों में हमने 15 आम चुनाव देखे हैं। किंतु, महिलाओं के वास्तविक चुनाव में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 7 से 11 प्रतिशत की सीमा में बना रहता है। स्वतंत्रता के 63 वर्षों के बाद आज भी 15वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10.7 प्रतिशत है। यह स्वयं इस मिथक को तोड़ देता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में स्थिति में धीरे–धीरे सुधार हो जाएगा, चाहे इस बारे में कुछ भी न किया जाए। सच्चाई यह है कि गत 63 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अगले 63 वर्षों में भी ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है।

बहुसंख्यक पुरुष भी महिलाओं के हित की देखभाल कर सकते हैं ?

सच्चाई यह है कि समाज का 50 प्रतिशत वर्ग 10 प्रतिशत शेयर प्राप्त करता है। हम वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की बात करते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक संख्या में अरबपति हैं। किंतु, हमारे दो–तिहाई बच्चे बिना चिकित्सा सुविधाओं के अपनी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं। माताओं की मृत्यु का अनुपात 1 लाख में से 410 है, जो संसार में सर्वाधिक है। लगभग 88 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं खून की कमी का शिकार रहती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से महिलाओं की संख्या का राष्ट्रीय औसत प्रत्येक 1000 पुरूषों पर 933 महिलाएं हैं। अपुष्ट रिपोर्ट दर्शाती हैं कि प्रति वर्ष 50 लाख भ्रूण हत्याएं कर दी जाती हैं। लैंगिक साक्षरता का अंतराल हमें विश्व में 121वें नम्बर पर रखता है हमारे देश की महिला साक्षरता 76 प्रतिशत पुरूष साक्षरता की तुलना में मात्र 53 प्रतिशत है। लड़कियां लड़कों से दोगुनी संख्या में स्कूल छोड़ देती हैं। यद्यपि गत 10 वर्षों में हमने अपने कुछ वैयक्तिक कानूनों में कुछ प्रगति की है। फिर भी कुछ वैयक्तिक कानून अभी भी प्रतिगामी हैं। वे महिलाओं को समान नहीं मानते हैं। कुछ कानून उन्हें संपत्ति समान अधिकार नहीं देते हैं। दहेज की बुराई अभी भी जारी

है। इस संसद में यह कहने का आज भी साहस नहीं है कि वे सभी वैयक्तिक कानून, जो सम्मान और समता के साथ जीने की सांविधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हैं, असांविधानिक हैं तथा उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।

इस तर्क में कोई दम नहीं है कि पुरूष भी महिलाओं के प्रति न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। कम प्रतिनिधित्व और भेदभाव हमारी आंखों के सामने हैं। समय आ गया है कि सबको समान प्रतिनिधित्व मिले। प्रतीकों की राजनीति को अब विचारों की राजनीति में परिवर्तित होना होगा। विचारों की राजनीति को प्रतिनिधित्व की राजनीति द्वारा गति प्रदान करनी होगी। यह वह तर्काधार है, जिस पर मैं इस बिल को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कानून क्या है ?

सांविधानिक संशोधन बेहद सीधा–साधा है। यह 15 वर्ष की अवधि के लिए है। इस 15 वर्ष की मियाद में यदि आम चुनाव समयानुसार होते है, तब लोकसभा सीटों के तीन ब्लॉक होंगे, जो प्रत्येक एक–तिहाई होगा। प्रत्येक ब्लॉक को एक आम चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व मिलेगा। 15 वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र महिला को संसद में भेज चुका होगा। क्योंकि अ.जा. तथा अज.जा. हेतु सीटों के प्रतिनिधित्व के वास्ते सांविधानिक उपबंध है, अतः उन आरक्षित सीटों का एक–तिहाई उन्हीं जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। यह सिद्धांत 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। प्रतिनिधित्व की मात्रा और गुणवत्ता का आंकलन करने के बाद भारतीय विधायिका को यह निर्णय करने का अवसर प्राप्त होगा कि आरक्षण को जारी रखा जाए या समाप्त किया जाए।

पिछला अनुभव

73वें और 74वें संशोधनों ने राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए थे। अनेक राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों तथा पंचायतों में 50 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित की हैं। महिला प्रतिनिधित्व में भी कई गुना विस्तार हुआ है। आज पंचायतों में 43 प्रतिशत निर्वाचित पदों पर महिलाएं आरूढ़ हैं।

अन्य देशों का अनुभव

विश्व के कई अन्य अनेक देशों का अनुभव दर्शाता है कि आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए तीन अलग–अलग प्रणालियों को अपनाया गया है। पहली प्रणाली महिलाओं के वास्ते नीयत निर्वाचित क्षेत्रों की कतिपय संख्या को आरक्षित किया जाना है। यह प्रणाली विश्वभर में सफल रही हैं। आज इस रिजर्वेशन की ताकत पर विश्व के एक निर्धनतम देश रवांडा ने संसद में 48.8 प्रतिशत महिलाएं भेजकर स्वीडन पर बाजी मार ली है। स्वीडन में 47 प्रतिशत, अर्जेंटीना में 40 प्रतिशत, नार्वे में 36 प्रतिशत तथा अफगानिस्तान में 27 प्रतिशत आरक्षण है जबकि, पाकिस्तान में यह आरक्षण 22 प्रतिशत है। निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित रखने की इस प्रणाली के कारण इसको सफलता मिली है।

दूसरी प्रणाली सूची प्रणाली है, जिसमें राजनीतिक दल दलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करते हैं। तीसरी पद्धति राजनीतिक दलों के लिए कोटा का नियत किया जाना है। इन सभी प्रणालियों को अपनाया गया है और वैश्विक पैटर्न भी उपलब्ध है।

राजनीतिक दलों के लिए महिला प्रत्याशियों हेतु प्रतिशतता निर्धारित करना क्यों सफल नहीं है

संविधान के अनुच्छेद 19(4) के तहत विहित सीमा के साथ पठित अनुच्छेद 19(1)(C) जिस रूप में इस समय अधिनियमित है, वह लिंगाधारित कोटा के साथ एसोसिएशन निर्मित करने तथा चलाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई विधान निर्धारित नहीं करता है, जो संविधान की दृष्टि से वैध हो, जो भी प्रतिबंध अनुमत है, वे भारत की संप्रभुता एकता सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिकता के हित में अनुमत है। ऐसी प्रणाली के सफल होने की संभावना नहीं है। यू.के. में ऐसी प्रणाली है। इसमें सुनिश्चित नहीं है कि महिलाओं को उन निर्वाचन क्षेत्रों से खड़ा किया जाए जहां उनके सफल होने की संभावना है। परिणाम यह होता है कि यू.के. की तरह के परिपक्व लोकतंत्र में, जो राजनैतिक दलों में कोटा विहित करता है, हाऊस ऑफ कामंस में प्रतिनिधित्व 19.8 प्रतिशत है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा रवांडा के प्रतिनिधित्व से कम है।

रोटेशन क्यों उचित है

संविधान संशोधन में रोटेशन हेतु उपबंध पर कुछ विवाद है। रोटेशन लिंग–आधारित आरक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। इससे सुनिश्चित होगा कि कि इस संशोधन के जीवन के 15 वर्षों की अवधि में देश का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम एक महिला प्रतिनिधि को संसद में भेजेगा। इससे देशभर में महिलाओं की सक्रियता में क्षैतिज फैलाव होगा। यह स्थानीय स्वशासनों और पंचायतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सक्रियता में भारी वृद्धि करेगा। इस प्रकार, 15 वर्ष के बाद जब आरक्षण समाप्त हो जाएंगे और निर्वाचन क्षेत्रों को खुला छोड़ दिया जाएगा तब भारत को राजनीतिक दलों के वास्ते लाखों महिला कार्यकर्ताओं में से छांटने की सुविधा मिलेगी। इसके विपरीत यदि कोई रोटेशन नहीं है तब एक निर्वाचन क्षेत्र ही लंबी समयावधि के लिए आरक्षित रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप उक्त निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित पुरूषों के विरूद्ध उलट भेदभाव हो जाएगा – उन पुरूषों के विरूद्ध जो काफी लंबी समयावधि के लिए अयोग्य हो जाएंगे। यह तर्क संगत नहीं है कि एक बार चुने गए व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल नहीं करेंगे। कोई भी महिला दूसरी बार चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की आमतौर पर देखभाल करेगी कि उसे अगला चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त है। ऐसे अनेक पुरूष प्रत्याशी होंगे, जो दूसरी बार चुनाव लड़ने की आशा में अपने निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल करने में व्यस्त होंगे।

क्या अन्य जातियों तथा समुदायों हेतु आरक्षण कोटा होना चाहिए

संविधान में केवल अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए जाति आधारित आरक्षणों की व्यवस्था है। जब अन्य समुदायों के लिए कोई आरक्षण नहीं है तब ऐसा कोई कारण नहीं हैं कि उन समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा छांटे गए अधिकांश प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्रों के सामाजिक स्वरूप को बिंबित करेंगे।

गुजरात प्रयोग

गुजरात विधानसभा ने एक विधेयक पास किया है, जिसमें स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण

की व्यवस्था है। विडंबना देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी केन्द्र में उक्त विधेयक का समर्थन कर रही है वही राज्य स्तर पर उसको बाधित कर रही है। विगत 4 मास से गुजरात की राज्यपाल विधेयक को अपनी सम्मति नहीं दे रही हैं। कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपनी प्रबिद्धता की कमी के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

इस सम्मानित सदन के सदस्य आज इस ऐतिहासिक विधान के पारित किए जाने के संन्निकट उपस्थित है। मैं आज की सरकार और भारत में महिलाओं की आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक का सर्वसम्मति से अनुमोदन करें।

माया सिंह

आदरणीय उपसभापति जी, मुझे याद है आज से 22 साल पहले पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में गांव–गांव तक मज़बूती के साथ उभरकर आएं, इसकी पहल की गई थी और बाद में 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर केंद्र सरकार ने पंचायती राज में एक–तिहाई महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी।

उस वक्त यह एक क्रांतिकारी पहल थी और इसके माध्यम से महिलाओं का एक न्या स्वरूप राजनीति में उभरकर सामने आया। बिहार सरकार ने इसके अच्छे परिणामों के कारण पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया और इसका अनुसरण अन्य प्रदेशों ने भी किया, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ राजस्थान, केरल और गुजरात की राज्य सरकारें शामिल हैं। इस आरक्षण के कारण ही गांवों के स्तर पर एक ओर तो महिलाओं में उम्मीद से ज्यादा जागरूकता पैदा हुई, दूसरी ओर पढ़ी–लिखी और अनपढ़, दोनों ही तरह की महिलाओं की नेतृत्व क्षमता भी सामने उभरकर आई। यह महिलाओं की इच्छाशक्ति और लगनशीलता का प्रतीक है कि आज गांवों में महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। वे घर के चौके–चूल्हे से लेकर प्रदेश के विकास में भी हाथ बंटा रही हैं।

उपसभापति जी, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पंचायतों के, स्वायत्त संस्थाओं के जो नगरीय चुनाव हुए हैं, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण गांवों में और शहरों में विकास की बागडोर 2,00,000 से ज्यादा महिलाओं के हाथ में आई है। वहां 1,80,000 से ज्यादा महिलाएं पंच बनी हैं, 11,520 महिलाएं सरपंच बनी हैं, 3,400 महिलाएं जनपद की सदस्य बनी हैं, 415 महिलाएं जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, 25 महिलाएं जिला पंचायत महिला अध्यक्ष बनी हैं, 1,780 महिलाएं पार्षद चुनकर आई हैं और हमारे यहां 8 महिलाएं नगर निगम की महापौर बनी हैं, जिसमें भोपाल में सामान्य महिला की जो सीट आरक्षित थी, उस पर ओबीसी की महिला महापौर चुनकर आई है। ये आंकड़े बताते हैं कि यह कितना क्रांतिकारी बदलाव है।

उपसभापति जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो सर्वप्रथम विधान सभा और संसद में महिलाओं की 33 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत बड़ौदा राष्ट्रीय परिषद में जून, 1994 में प्रस्ताव पास करके की। महोदय, उस समय महिलाओं को यह जानकारी भी नहीं थी कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए इस तरीके का कोई प्रस्ताव हमारी पार्टी पास करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए यह प्रस्ताव पास किया और इसके बाद हमारी पार्टी ने संगठन में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देकर राजनीति में आगे बढ़ाने का काम पहले से ही शुरू कर दिया। मुझे याद है कि एन.डी.ए. के कार्यकाल में दो बार पूर्व प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विधेयक को पास कराने के लिए आम सहमति बनाने के प्रयास किए और सुषमा स्वराज जी, जो उस समय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर थीं, उन्होंने इसके लिए बेहद परिश्रम किया और इसे संसद में चर्चा के लिए रखा, पर उस वक्त हमें सफलता नहीं मिली। महोदय, इस महिला आरक्षण विधेयक का मेरी पार्टी समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में आरक्षण देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में निर्णायक भूमिका देने की पक्षधर रही है।

हम कोई राजनैतिक खेल खेलना नहीं चाहते और न ही श्रेय लेने की होड़ में इस विधेयक में रोड़ा डालना या अवरोध पैदा करना चाहते हैं, बल्कि जो दल विरोध कर रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन और सुधार की गुंजाइश हमेशा हो सकती है। संसद में बहस के दौरान सभी दल अपनी भावनाओं और विचारों को रखते हुए विधेयक में उसे समाहित करने का प्रयास करें। लेकिन मेरा यह भी आग्रह है कि इस विधेयक को उसके वर्तमान स्वरूप में ही पास करवाया जाए। आने वाले समय में अनुभव के आधार पर विधेयक में संशोधन और परिमार्जन किए जाने की संभावना सर्वथा बनी रहेगी। उपसभापति महोदय, पिछले कई वर्षों से संसद में महिला आरक्षण विधेयक लम्बित रहने से आम जनता में यह संदेश जा रहा है कि हमारी संसद महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि इसी संसद ने महिलाओं के हितों और अधिकारों की रक्षा तथा उनकी तरक्की के लिए कई कानून बनाए हैं। इसीलिए मेरी सबसे यह अपील है, मैं सबसे यह आग्रह करना चाहती हूं कि सब इस विधेयक के प्रति उदार भाव रखें ताकि इसके पारित होने की सूरत उभर सके। महोदय, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस विधेयक की पक्षधर रही है। आज, जब सदन में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है और इस पर मैं अपनी बात रख रही हूं तो इस विधेयक पर अपने विचार रखते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। लेकिन दो दिन का जो घटनाक्रम था, उसने जो पीड़ा पहुंचाई है, अगर हम पहले से इसका थोड़ा सा होमवर्क कर लेते तो शायद ऐसी कटुतापूर्ण स्थिति न आती और हमें उन भाइयों का, उन

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित

'अनुभव और ऊर्जा' का अद्भुत संगम

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 16 मार्च, 2010 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं संसदीय बोर्ड के गठन की घोषणा की। श्री गडकरी द्वारा पार्टी मुख्यालय पर घोषित कार्यकारिणी में 121 सदस्य, 13 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 15 सचिव एवं 1 कोषाध्यक्ष शामिल हैं। महिलाओं को संगठन में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर अमल करते हुए श्री गडकरी ने अपने पदाधिकारियों की सूची में 13 महिलाओं को जगह दी है। कुल मिलाकर 40 महिला कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया गया है।

उपाध्यक्ष

1. Jh 'kkrk dekj % आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। आप पूर्व में एनडीए सरकार में केन्द्रीय खाद्य मंत्री एवं हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

2. Jh dyjkt feJ % वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। आप पूर्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। पूर्व में भाजपा संगठन की ओर से विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी के रूप में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

3. Jh fou; dfV;kj % आप पूर्व में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। आपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन किया है। आप लोकसभा के सांसद भी रहे हैं।

4. Jh Hkxrflag dks';kjh % वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। आप पूर्व में उत्तराखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

5. Jh e[rkj vCckl udoh % आप पूर्व में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पार्टी के प्रवक्ता रहे। आप एनडीए सरकार में केन्द्रीय मंत्री भी रहे।

6. Jherh d:.kk 'kDyk % आपने पूर्व में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। आप महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं लोकसभा की सांसद भी रही हैं।

7. Jherh utek girYyk % वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। इसके पूर्व दो बार राज्य सभा के उपसभापति के रूप में सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन किया है।

8. Jherh gek ekfyuh % आप राज्यसभा सांसद रही हैं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हैं। गत कई चुनावों में भाजपा की स्टार प्रचारिका के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

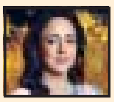

9. Jherh fot;k pØorh % वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। पूर्व में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री रही। एनडीए सरकार में आप ने केन्द्रीय राज्यमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन किया है।

10. Jh i:"kkÙke :ikyk % वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। आप पूर्व में गुजरात सरकार में मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं।

11. Jherh fdj.k ?kbi % आप पूर्व में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री रही हैं। भाजपा बिहार प्रदेश की प्रवक्ता रही हैं।

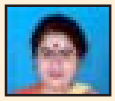

12. ....., 13.....

महामंत्री

1. Jh vur dekj ¼ वर्तमान में लोकसभा के पांचवी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। आप पूर्व में भी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। एनडीए सरकार में आप केन्द्रीय मंत्री भी रहे।
2. Jh Fkkojpn xgykr ¼ आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तथा लोकसभा के सांसद भी रहे हैं।
3. Jherh olqa/kjk jkts ¼ आप राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आप पूर्व में एनडीए सरकार में केन्द्रीय मंत्री रही। राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।
4. Jh fot; xks;y ¼ आप पूर्व में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। आपने एनडीए सरकार में केन्द्रीय राज्य मंत्री के पद पर अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।
5. Jh vtZqu eq.Mk ¼ आप लोकसभा के सांसद हैं। पूर्व में झारखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने राज्यविधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी अपने दायित्वों का सफलता पूर्वक निर्वहन किया है।
6. Jh jfo'kadj izlkn ¼ (मुख्य प्रवक्ता) आप राज्यसभा में भाजपा के सांसद हैं। पूर्व में एनडीए सरकार में केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं।
7. Jh èkesZUnz iz/kku ¼ आप भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं। आप पूर्व में लोकसभा के सांसद भी रहे।
8. Jh ujsUnz rkej ¼ आप वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं एवं पूर्व में मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं।
9. Jh txr izdk'k uM~Mk ¼ आप हिमाचल सरकार में मंत्री रहे। पूर्व में हिमाचल प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता एवं भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं।
10. Jh jkeyky ¼laxBu½ ¼ आप भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) हैं। पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रहे हैं।
11. Jh oh- lrh'k ¼lg laxBu egkea=h½ ¼ आप पूर्व में भी भाजपा के सह संगठन महामंत्री रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं।
12. Jh lkSnku flag ¼lg laxBu egkea=h½ ¼ आप पूर्व में भी भाजपा के सह संगठन महामंत्री रहे। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री रहे।

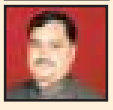

मंत्री

1. Jh larks"k xaxokj ¼ आप पूर्व में लोकसभा के सांसद रहे हैं। आप एनडीए सरकार में केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। आप लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक भी रहे।
2. Jherh Lefr bZjkuh ¼ आप पूर्व में भी भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री रही हैं। विभिन्न चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी का प्रचार करती रही हैं। आप छोटे पर्दे की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं।
3. dqekjh ljkst ik.Ms ¼ आप लोकसभा में सांसद हैं। इसके पूर्व दो बार मेयर एवं विधायक निर्वाचित हो चुकी हैं। आप पूर्व में भी भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री रही एवं भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश की महामंत्री एवं प्रवक्ता रही हैं।
4. Jherh fdj.k ekgs'ojh ¼ आप वर्तमान में राजस्थान से विधायक हैं। आप पूर्व में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही। आप लोकसभा की सांसद भी रही हैं।
5. Jh rkfij xko ¼ आप पूर्व में अरूणाचल प्रदेश से लोकसभा के सांसद रहे। उत्तर–पूर्व के प्रमुख भाजपा नेता हैं।
6. Jh uothr flag fl)w ¼ आप लोकसभा के सांसद हैं। आप ने विभिन्न चुनाव में भाजपा के प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। आप प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। वर्तमान में भी छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार हैं।
7. Jh v'kksd iz/kku ¼ आप उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दलित नेता हैं। आप पूर्व में एनडीए सरकार में केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे।
8. Jh o:.k xka/kh ¼ वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं। भाजपा के युवा नेता हैं।
9. Jh ejyhèkj jko ¼ आप पूर्व में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं।
10. Jh fdjhV lkSe;k ¼ आप पूर्व में लोकसभा के सांसद रहे। आप प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं।
11. Mk- y{e.k ¼ आप भाजपा आंध्रप्रदेश के महामंत्री रहे। आपने आंध्रप्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।
12. dSIVu vfHkeU;q ¼ आप पूर्व में भाजपा हरियाणा प्रदेश के महामंत्री रहे हैं। आप मीडिया जगत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं।
13. Jherh vkjrh egjk ¼ आप दिल्ली की पूर्व मेयर रही हैं। आप भाजपा दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा भी रह चुकी हैं।

14. Jh HkiUn ;kno ¼ आप पूर्व में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं।

15. dekjh ok.kh f=ikBh ¼ आप पूर्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही हैं। आप फिल्म अभिनेत्री हैं।

कोषाध्यक्ष

Jh ih;"k xks;y ¼ आप पूर्व में भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के कोषाध्यक्ष एवं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं।

प्रवक्ता

1. श्री प्रकाश जावडेकर
2. श्री राजीव प्रताप रूड़ी
3. श्री शाहनवाज हुसैन
4. श्री रामनाथ कोविंद
5. श्री तरूण विजय
6. श्रीमती निर्मला सीतारमन

सदस्य

1. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
2. श्री लालकृष्ण आडवाणी
3. डॉ. मुरली मनोहर जोशी
4. श्री बंगारू लक्ष्मण
5. श्री वेंकैया नायडू
6. श्री राजनाथ सिंह
7. श्रीमती सुषमा स्वराज
8. श्री अरुण जेटली
9. श्री बाळ आपटे
10. श्री यशवंत सिन्हा
11. श्री गोपीनाथ मुण्डे
12. श्री एस.एस. अहलूवालिया
13. श्री अरुण शौरी
14. श्री बलबीर पुंज
15. श्री चंदन मित्रा
16. श्रीमती मृदुला सिन्हा
17. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
18. श्री कप्तानसिंह सोलंकी
19. श्रीमती सुमित्रा महाजन
20. श्रीमती जयवंतीबेन मेहता
21. डॉ. विनय सहस्रबुद्धे
22. श्री शेषाद्रिचारी
23. श्रीमती अनिता आर्य
24. डॉ. सी.पी. ठाकुर
25. श्री दिलीप सिंह जुदेव
26. श्रीमती सुधा यादव
27. श्री रामथाल चौधरी
28. श्रीमती मेनका गांधी
29. श्री योगी अदित्यनाथ
30. श्री लालजी टंडन
31. श्री हुकुमदेव नारायण यादव
32. डॉ. जे.के. जैन
33. डॉ. अनिल जैन
34. श्री अरुण सिंह
35. श्री नलिन कोहली
36. श्री जयप्रकाश अग्रवाल (सूर्या)
37. श्रीमती पूनम आजाद
38. श्रीमती रेखा गुप्ता
39. श्रीमती पिंकी आनंद
40. श्री हरि बाबू
41. श्रीमती शांता रेड्डी
42. श्रीमती सुखदा पांडे
43. श्री भुपेन्द्र सिंह चुदासामा
44. श्री बालूभाई शुक्ला
45. श्री ओमप्रकाश धनकड़
46. श्री विनोद खन्ना
47. श्रीमती किरण खेर
48. श्री अर्जुन मेघवाल
49. श्री सुभाष मेहरिया
50. श्रीमती सुमन श्रींगी
51. श्री मानवेन्द्र सिंह
52. श्री ओमकार सिंह लखावत
53. श्री एच. राजा
54. श्रीमती ललिता कुमारमंगलम
55. श्री एम.टी. रमेश
56. श्री सी. एच. विजय शंकर
57. श्रीमती गौरी चौधरी
58. श्री विजय महापात्रा
59. श्रीमती सुरमा पाढ़ी
60. श्रीमती शोभाताई फणनविस
61. श्री महेश जेठमलानी
62. श्रीमती साइना एन.सी.
63. श्रीमती मनीषा चौधरी
64. श्री नैना समकुल
65. श्रीमती कांता नलवाडे
66. श्रीमती लुईस मरांडी
67. श्री सुनील सिंह
68. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
69. श्री विरेन्द्र कुमार खटिक
70. श्रीमती निर्मला भुरिया
71. श्री सतपाल मलिक
72. डॉ. विनय सोनकर शास्त्री
73. श्री मनोज सिन्हा
74. श्रीमती सरला सिंह
75. श्री रामबक्स वर्मा
76. श्री हुकुम सिंह
77. श्री सुधांशु त्रिवेदी
78. साध्वी निरंजना ज्योति
79. श्री अजय टामटा

80. श्रीमती शांति मेहरा
81. कुमारी रंजना शाही

स्थायी सदस्य

मुख्यमंत्री

1. श्री नरेन्द्र मोदी
2. श्री शिवराज सिंह चौहान
3. डॉ. रमन सिंह
4. श्री प्रेमकुमार धूमल
5. श्री बी.एस. येदियुरप्पा
6. श्री रमेश पोखरियाल निशंक

उप मुख्यमंत्री

7. श्री सुशील मोदी
8. श्री रघुबर दास

पूर्व- संयाजक

9. श्री केदारनाथ साहनी
10. श्री कैलाशपति मिश्रा
11. श्री वी. रामा राव

पूर्व मुख्यमंत्री

12. श्री सुंदरलाल पटवा
13. श्री केशुभाई पटेल
14. श्री मदनलाल खुराना
15. श्री बी.सी. खंडूरी
16. श्री नित्यानंद स्वामी
17. श्री कैलाश जोशी
18. श्री बाबूलाल गौर
19. श्री मनोहर पर्रिकर

विधान मंडल के नेता

20. श्री गंगा प्रसाद
21. डा. वी. एस. आचार्य
22. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा
23. श्री एकनाथ खडसे
24. श्री भाऊसाहब फुडकर
25. श्री घनश्याम तिवारी
26. श्री ओमप्रकाश सिंह
27. श्री नेपाल सिंह
28. श्री मिशन रंजन दास
29. श्री चमनलाल गुप्ता
30. श्री के.वी. सिंहदेव
31. श्री मनोरंजन कालिया
32. श्री तमिगो तागा, (अरूणाचल प्रदेश)
33. श्री अनिल विज

मुख्य सचेतक (संसदीय दल)

34. श्री रमेश बैस
35. श्रीमती माया सिंह

संसदीय दल के कार्यालयमंत्री एवं सह कार्यालय मंत्री

36. श्री रामकृपाल सिन्हा
37. श्री षडमुगनाथन

अन्य सदस्य

38. श्री ओ. राजगोपल
39. डा. सत्यनारायण जटिया
40. श्री केसरीनाथ त्रिपाठी
41. श्री देवदास आपटे (बापू आपटे)
42. श्री सदानन्द गौडा
43. श्री तनवीर हैदर उस्मानी
44. डा. हर्ष वर्धन
45. श्री विद्यासागर राव
46. श्री बंडारू दत्तात्रेय
47. श्री विनोद पाण्डे
48. श्री एम. भरोत सिंह
49. श्री राजन गोइन
50. श्री रमन डेका
51. श्री निलमनी देव
52. श्री विष्णुदेव साय
53. श्री नरेश बंसल
54. श्री हरेन्द्र प्रताप
55. श्री रामबिलास शर्मा
56. श्री महेश्वर सिंह
57. डॉ. निर्मला सिंह
58. श्री राजेन्द्र भण्डारी
59. श्री सत्यपाल जैन
60. श्री गुलाबचंद कटारिया
61. श्री रामदास अग्रवाल
62. श्री एल. गणेशन
63. श्री सी.के. पद्मनाभन
64. श्री तथागत राय
65. श्री श्रीपाद येशु नायक
66. श्री रामप्यारे पाण्डे
67. श्री अनंत नायक
68. श्री प्रकाश मेहता
69. श्री विनोद तावडे
70. श्री अमित ठक्कर
71. श्री सुरेश पुजारी
72. श्री आर. रामकृष्णा
73. श्री ओमप्रकाश कोहली
74. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी
75. श्री अशोक खजुरिया
76. श्री मांगेराम गर्ग
77. श्री जगदीश मुखी

विशेष आमंत्रित

1. श्री पद्नाभ आचार्य
2. श्री सुकुमार नाम्बियार
3. श्री बलराम दास टंडन

4. श्री विजय कपूर
5. श्री अरुण साठे
6. श्री नन्द किशोर गर्ग
7. डॉ. वामनाचार्य
8. श्री जगदीश शेट्टीगर
9. श्री आलोक कुमार
10. श्री अरुण अदसद
11. श्री एस. सुरेशकुमार
12. श्री सी.एस.पर्चा
13. श्री गजेन्द्र चौहान
14. श्रीमती आनन्दीबेन पटेल
15. श्री अमित शाह
16. श्री किशनसिंह सांगवान
17. श्री गोविन्द कर्जल
18. श्री रामजी ऋषिदेव
19. श्री बनवारीलाल पुरोहित
20. श्री हरिभाऊ बगडे
21. श्री चैतन्य कश्यप
22. श्री हृदयनारायण दीक्षित
23. श्री तनवीर अहमद
24. श्री राजेश शाह
25. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
26. श्री भूपेन्द्र ठाकुर
27. श्री हरजित सिंह ग्रेवाल
28. श्री रविकांत गर्ग
29. श्री सुवर्ण सलेरिया
30. श्री क. बैंसला
31. श्री सिद्धार्थनाथ सिंह
32. श्री उदय भास्कर नायर
33. श्रीमती कविता खन्ना
34. श्री अमिताभ सिन्हा
35. श्री आशुतोष वैष्णव
36. श्री अजय संचित
37. श्री राधामोहन सिंह
38. श्री नन्द किशोर यादव

संसदीय बोर्ड

1. श्री नितिन गडकरी,
2. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
3. श्री लालकृष्ण आडवाणी
4. डॉ. मुरली मनोहर जोशी
5. श्री वेंकैया नायडू
6. श्री राजनाथ सिंह
7. श्रीमती सुषमा स्वराज
8. श्री अरुण जेटली
9. श्री बाळ आपटे
10. श्री अनंत कुमार
11. श्री थावरचंद गहलोत
12. श्री रामलाल

■

प्रतिपक्ष से घबराई केन्द्र की यूपीए सरकार

लोकसभा में विपक्ष की नेता, श्रीमती सुषमा स्वराज एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

बजट सत्र का प्रथम हिस्सा, जो कि 16 मार्च 2010 को सम्पन्न हुआ, भारत की प्रतिपक्षी पार्टियों के लिए इस रूप में एक अवसर सिद्ध हुआ कि इसके द्वारा उन्होंने यूपीए सरकार की आवश्यक वस्तुओं (विशेषकर खाद्य वस्तुओं) के बढ़ते हुए दामों को नियंत्रित करने की अक्षमता से आहत हुए लोगों के बारे में जानकारी दी। सदन में समन्वय विपक्ष की महत्वपूर्ण विशेषता रही। सदन में समन्वय की पूर्णरूपेण अनुपस्थिति यूपीए के कार्यचालन की विशेषता रही। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में भाजपा ने अपने कर्त्तव्यों को प्रभावी रूप में निभाकर संतोष का अनुभव किया।

सरकार के आर्थिक एजेंडा प्रस्तुत करने के उपरांत होने वाली एक प्रभावी बहस संसद में विरले ही देखी गई है। यह बहस, भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए मौका था। जब थोक मूल्य सूचकांक दो अंकों पर जा रहा था और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी उसी अनुपात में बढ़ रहा था, तब सरकार के पास सिर्फ झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नही था। बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों अर्थात् तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ शुल्कों में बढ़ोत्तरी, सेवा कर में लगातार वृद्धि से मुद्रास्फीति को और बढ़ावा मिलेगा। बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने में असफलता से यूपीए सरकार की अयोग्यता स्पष्ट रूप से सिद्ध हुई। लोकसभा में शोर शराबे के बीच विनियोग विधेयक और रेलवे बजट को पारित कराना यूपीए सरकार की विस्तृत चर्चा को टालने की नीति थी। यूपीए सरकार कोई जवाब नहीं दे सकती थी और यहां तक कि मंहगाई पर कोई उत्तर दिया भी नही जा सकता था। राज्यसभा में सरकार को सामान्य और रेलवे दोनों बजटों पर असहज प्रश्नों का सामना पड़ा।

महिलाओं को लोकसभा और राज्य, विधान मंडलों में आरक्षण देने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करना यूपीए सरकार की सदन प्रबंधन का विफल प्रयास था। यह विधेयक उस बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया, जहां सरकार अल्पमत में थी और विपक्ष बहुमत में था। ज्यादातर मुख्य विपक्षी पार्टियां इस विधेयक के समर्थन में थी। यूपीए पहले तो अनिश्चिय की स्थिति में रही और जब विधेयक के साथ आगे आई तो सार्थक बहस से बचते हुए और मार्शल की सहायता से बगैर किसी चर्चा के इस विधेयक को पारित कराने पर अड़ गई। भाजपानीत विपक्ष ने चर्चा करने पर जोर दिया। भाजपा विधेयक के लिए प्रतिबद्ध थी। भाजपा जोरदार तरीके से और स्पष्ट रूप में विधेयक से समर्थन में आई परन्तु, भाजपा सदन की गरिमा को भी बनाए रखना चाहती थी। अंत में महिलाओं के आरक्षण के मुददे पर भाजपा के नेतृत्व में यह विधेयक राज्य सभा में कुछ कदम आगे बढ़ा और राज्यसभा में यह विधेयक विपक्ष के हावी होने और सरकार के कुप्रबंधन के बावजूद अनुमति प्राप्त कर सका।

सिविल स्वतंत्रता हेतु न्यूक्लीयर डैमेज़ बिल (2009) जोकि लोकसभा में 15 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित किया जाना था, वह भी सरकार की सदन के कमजोर प्रबंधन का एक और उदाहरण रहा। यह माना जाता है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। फिर भी, इसके समर्थकों की संख्या कम रही। प्रतिपक्ष ने मिलजुलकर सरकार द्वारा सदन के कमजोर प्रबंधन का पर्दा फाश कर दिया। प्रतिपक्ष ने मिलकर घबराई यूपीए सरकार को पीछे हटने के लिए विवश किया। हमको आशा है कि इस विधेयक के प्रति एकजुट हुआ प्रतिपक्ष सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करेगा। ■

दलों का समर्थन भी मिलता, या उनकी सहमति भी हो सकती। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम आज इस विधेयक का जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं...।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भी उसी जिम्मेदारी का परिचय देकर इस विधेयक का समर्थन करती तो एनडीए के शासनकाल में ही यह विधेयक पारित हो गया होता और इसका लाभ हमारे देश की महिलाएं ले रही होतीं। यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है, जो हमारे संविधान निर्माताओं के उस सपने को मूर्त रूप देगा, जो महिलाओं और पुरूषों के बीच में गैर–बराबरी को मिटाने की हसरत रखता था। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय समाज में महिलाएं किस तरीके से अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और दूसरी नागरिकता का शिकार रही हैं। संसद के भीतर और बाहर महिलाओं के हितों और अधिकारां की रक्षा के जो भी प्रयास हुए हैं, उनमें से महिला आरक्षण विधेयक एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा जो उन्हें राजनैतिक और शासन चलाने की प्रक्रिया में अधिकार सम्पन्नता के साथ सबद्ध करता है। दुनिया भर में चल रहे नारी मुक्ति आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलनों से भी आगे बढ़कर यह महिलाओं को अधिकार देगा। सर, आजाद भारत के इतिहास में महिलाओं को मजबूत करने का, महिलाओं के सशक्तिकरण का हमारा इतिहास रहा है। आज जब संसद में महिलाओं को यह कानूनी अधिकार मिलने जा रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक प्रसंग की मूक गवाह नहीं है, बल्कि इसकी सक्रिय भागीदार बनने जा रही है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस महिला आरक्षण विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूं और अन्य दलों से अपेक्षा करती हूं तथा उनसे आग्रह करती हूं कि वे भी इस विधेयक का समर्थन करें ताकि यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। ■

केंद्र की यूपीए सरकार में इच्छाशक्ति नहीं : राजनाथ सिंह

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार, नक्सलवाद व आतंकवाद को मिटाने में कांग्रेस सरकार में इच्छाशक्ति का अभाव है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार व आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। श्री राजनाथ सिंह भाजपा जिला कार्यालय, मिरजापुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा सरकारों ने प्रदेश ही नहीं, देश की व्यवस्था को कबाड़ बना दिया है। यही कारण है कि आतंकवाद, नक्सलवाद व भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस में इससे मुकाबला करने की क्षमता नहीं है, उसमें दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव है। श्री सिंह ने प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती द्वारा रुपयों का माला पहनने पर कहा कि नेता का सम्मान होना गलत नहीं है, लेकिन धन का इस तरह प्रदर्शन अच्छा नहीं है। मायावती सरकार संकीर्ण भावनाओं से घिर गई है। यही कारण है कि विकास में असंतुलन है। महिला आरक्षण के मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो बिल राज्यसभा में पास करवाया है, उसका मसौदा पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ही तैयार करवाया, उन्होंने मजहब के आधार पर आरक्षण देने का प्रबल विरोध करते हुए कहा कि एक बार मजहब के आधार पर देश का विभाजन हो चुका है। अब ऐसा कोई भी निर्णय भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। हेडली के प्रकरण पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की कूटनीतिक विफलता है। ■

महिला आरक्षण पर कांग्रेस कर रही है पाखंड : किरण माहेश्वरी

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती किरण माहेश्वरी ने कहा कि विगत 15 वर्षों से कांग्रेस महिला आरक्षण पर पाखंड की राजनीति कर रही है। सदन में हो–हल्ला करने वाले सदस्य कांग्रेस के समर्थक दलों के ही है। पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के शोर–गुल के मध्य भी सरकार ने पारित करवाए थे। सर्वदलीय बैठक के बहाने कांग्रेस महिला आरक्षण को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है।

आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महिला मोर्चा द्वारा 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल पास न होने पर सैंकड़ों की तादाद में महिला कार्यकताओं ने अपनी गिरफ्तारी संसद के बाहर दी। महिलाओं का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सरिता चौधरी ने किया। प्रदर्शन में महामंत्री रेखा गुप्ता एवं पार्षद बहनें तथा बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं संसद पर इकट्ठी हुईं तथा अपनी मांग प्रधानमंत्री को बताना चाहती थीं, परंतु बीच में ही पुलिस द्वारा रोक लिया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी ने कहा कि सरकार भविष्य में महिलाओं के साथ मजाक बंद करें अन्यथा भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा तथा बिल को पास करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।

महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षा, श्रीमती सरिता चौधरी ने कहा, कि उन्हें सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है अन्यथा बहुमत होने पर भी बिल का पास न होना कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी दिखाता है। महिलाओं को संसद में, विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिल का समर्थन करना अपनी भूमिका का सकारात्मक तरीके से निर्वहन है तथा भाजपा चाहती है कि यह बिल तुरंत पास होना चाहिए। ■

परमाणु क्षतिकारक बिल २०१० असंवैधानिक : यशवंत सिन्हा

भाजपा के वरिष्ठ सांसद श्री यशवंत सिन्हा ने ''सिविल लाइबिलिटी फार न्यूक्लियर डेमेज बिल 2010'' पर 15.3.2010 को लोकसभा सदन में पेश किए जाने पर आपत्ति प्रगट करने के लिए लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल (महासचिव) को एक विस्तृत पत्र लिखते हुए कहा है कि यह बिल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 14 के अतिक्रमण के अलावा भी यूएन चार्टर का उल्लंघन करता है। उन्होंने सदन में पेश होने से पूर्व अपनी आपत्ति प्रगट करने की अनुमति चाही है। मूल पाठ का भावानुवाद नीचे प्रस्तुत है:–

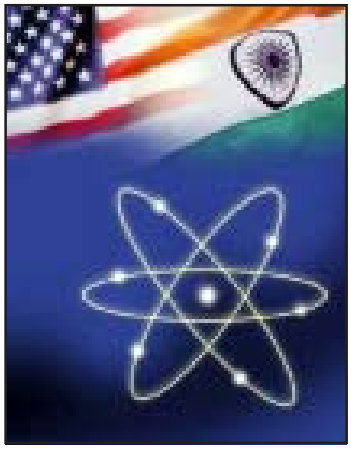

'सिविल लाइबिलिटी फार न्यूक्लियर डेमेज बिल 2010' को आज (15.3. 2010) की कार्य सूची में पेश करने के लिए शामिल किया गया है। इस बिल को सदन में पेश नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे भारतीय संविधान का कई प्रकार से स्पष्ट अतिक्रमण हो रहा है। पहला अतिक्रमण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का है जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 'जीने के अधिकार' को ''मानव गरिमा'' के जीने के अधिकार के रूप में व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने ओलियम गैस रिसाव मामले में निर्णय देते हुए कहा था कि ''जब कोई उद्यम किसी ऐसे खतरनाक उद्योग से जुड़ा होता है जिसमें फैक्टरी में काम करने वाले व्यक्तियों और आस–पास के क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा पहुंचने की संभावना बनी रहती है तो उस उद्यम का परम और अप्रयायोजित कर्त्तव्य बनता है कि समुदाय को उस उद्योग की गतिविधियों से किसी प्रकार की खतरनाक और उसमें निहित अन्य कोई संकटपूर्ण स्थिति का कार्य न किया जाए।'' 1996 में इंण्डियन कौंसिल फार एनवायरो–लीगल एक्शन'' के मामले में कोर्ट की व्यवस्था थी कि चलाई जा रही किसी भी गतिविधि में उसकी प्रकृति का दायित्व पूर्णतः समाहित रहता है। इसमें ''प्रदूषण फैलाने वाले को भुगतान करने का सिद्धांत'' आवश्यक है जिसमें इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से जो भी विध्वंस पैदा होता है या उसके किसी उपचारी कार्य के लिए सरकार की तरफ से भुगतान करने की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि ऐसा करने का मतलब यह होगा कि इस प्रकार की गतिविधियों का आर्थिक कर दाताओं पर बोझ डाला जाए।

प्रख्यात जूरिस्ट (न्यायशास्त्री) श्री सोली सोराबजी के अनुसार ''सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों का प्रभाव यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मौलिक अधिकारों के रूप में दुर्घटना के पीडितों की क्षतिपूर्ति और सुरक्षा करना आवश्यक है। हमारे संविधान के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देश का कानून होते हैं और सभी न्यायालयों, अधिकरणों और व्यक्तियों के लिए इनका अनुपालन बाध्यकारी होता है।''

बिल की धारा 6 में 300 मिलियन एसडीआर 458 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष रूपयों तक दायित्व और 500 करोड़ (109 अमरीकी डालर) के आप्रेटर के दायित्व तक सीमित रखा गया है। इस प्रकार, इससे न केवल दायित्व सीमित होता है बल्कि सरकार के दायित्वों का एक बहुत बड़ा भाग भी, दूसरे शब्दों में करदाता का दायित्व का हस्तांतरण होता है। प्राइस एंडरसन एक्ट आफ दि यूएस के अन्तर्गत आप्रेटर का दायित्व 12.5 बिलियन डालर है जो इण्डियन आप्रेटर के निर्धारित दायित्व से 23 गुना अधिक है। स्पष्ट है कि अमरीकी जीवन की तुलना में भारतीय जीवन को दशमांस माना गया है। इस प्रकार इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण होता है जिसमें विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का निर्धारण है। हम अपने नागरिकों के लिए दो व्यवस्थाएं नहीं बना सकते हैं जिसमें एक में तो देश की विधि के अनुसार विभिन्न उद्योगों के लिए पूरी क्षतिपूर्ति का अधिकार रखा जाए तो दूसरे में किसी खास राशि तक इस क्षतिपूर्ति को सीमित रखा जाए।

इससे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अतिक्रमण भी होता है, जिस पर हमने 30 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। चार्टर में मौलिक अधिकारों में, प्रतिष्ठा में और मानव–व्यक्ति में आस्था रखी गई थी और स्पष्ट निर्धारण है कि सभी महिलाओं और पुरुषों एवं सभी छोटे–बड़े राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अतः प्रसतावित बिल हमारे संविधान और यूएन चार्टर का स्पष्ट अतिक्रमण है और सदन में पेश नहीं किया जा सकता है।

कृपया सदन में बिल पेश होने से पूर्व मुझे इस पर अपनी आपत्ति प्रगट करने की अनुमति दें। ■

अंध मोदी-विरोध का अर्थ

,l 'kdj

lkल भर भी नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त इसी विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कुख्यात मानवाधिकारवादी तीस्ता सीतलवाड को गुजरात के बारे में भयानक हत्याओं और उत्पीड़न की झूठी कहानियां गढ़ने, झूठे गवाहों की फौज तैयार करने, अदालतों में झूठे दस्तावेज जमा करवाने और पुलिस पर मिथ्या आरोप लगाने का दोषी ठहराया था। पर उस रिपोर्ट के बाद तीस्ता के विरुद्ध कुछ नहीं हुआ। अब उसी दल ने नरेंद्र मोदी को मात्र बयान देने के लिए बुलाया, तो इसी आधार पर उनसे इस्तीफा देने की मांग होने लगी!

एक ऐसा व्यक्ति जो जाने–अनजाने हिंदू आत्मरक्षा का प्रतीक बना, जिसने एक छोटा–सा सच कहने की हिम्मत की, उसे भारत में राजनीतिक अछूत बना दिया गया है! उसकी ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा, निष्पक्ष–प्रशासन और जन–समर्थन के बावजूद प्रभावी राजनीतिक–बौद्धिक वर्ग में उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं। यह एक खतरनाक स्थिति है।

इस अंध मोदी–विरोध को कैसे समझा जाना चाहिए? पांच वर्ष पहले नाटककार विजय तेंदुलकर ने कहा था कि यदि वे पिस्तौल उठाएंगे तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को मारेंगे। देश के बौद्धिक–राजनीतिक वर्ग ने तेंदुलकर की निंदा नहीं की। उलटे मोदी को बुरा–भला कहा। इनमें वे भी थे जो मानवाधिकार और सामुदायिक सद्भाव के लिए आतंकियों को भी सुविधा व छूट देने की मांग करते हैं। मोदी लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बने तो इसमें उनके अच्छे शासन का भी योग है। इसके बावजूद राजनीतिक वर्ग में उनके प्रति विद्वेष और उन्हें कानून या मीडिया द्वारा फांसने की कोशिशें भी कम नहीं हुई हैं। इसका अर्थ है कि आज भी मोदी अकेले हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जाने–अनजाने हिंदू आत्मरक्षा का प्रतीक बनाए जिसने एक छोटा–सा सच कहने की हिम्मत की, उसे भारत में राजनीतिक अछूत बना दिया गया है! उसकी ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा, निष्पक्ष–प्रशासन और जन–समर्थन के बावजूद प्रभावी राजनीतिक–बौद्धिक वर्ग में उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं। यह एक खतरनाक स्थिति है। मोदी केवल चुनावी आधार पर विजयी रहे हैं, क्योंकि गुजराती जनता उनके पक्ष में है। इसके अलावा हर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके खिलाफ जहर उगला जाता है।

इस अखंड मोदी–विरोध ने उन हिंदुओं को डराया है जो हिंदू चिंताओं को मुस्लिम चिंताओं के समान देखना उचित समझते हैं। यह संयोग नहीं कि जो बुद्धिजीवी, पत्रकार और राजनीतिकर्मी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जिहाद में लगे हैं, वे ऐसे एनजीओ के कर्ता–धर्ता हैं जिन्हें संदिग्ध विदेशी स्त्रोतों से धन, पुरस्कार मिलता है। तीस्ता सीतलवाड को निरंतर सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें पुरस्कृत करने का संदेश यही है कि देश हिंदू–विरोधियों का है। इसलिए हिंदुओं में भी जो सेक्यूलर–वामपंथ, मानवाधिकारवाद, वैश्विक नागरिक, बहुंसस्कृतिवाद आदि के नाम पर व्यवहारतः हिंदू–विरोधी हो चुके हैं, उन्हीं को प्रश्रय मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो सहज हिंदू भावना, न्याय भावना से बोलेंगे उन्हें लताड़ा जाएगा। मोदी–विरोध एक वृहत वैचारिक–राजनीतिक रणनीति का अंग है। वह अलग बिंदु नहीं, बल्कि एक असहिष्णु तानाशाही की अभिव्यक्ति है, जो मानो भारतीय हिंदुओं को चेतावनी दे रही है कि विश्व में हिंदू समुदाय या हित जैसी चीज नहीं। इसलिए उसके अधिकार तो क्या, सामान्य अभिव्यक्ति भी सांप्रदायिकता और दूसरों के अधिकारों का हनन है! मोदी को कदम–कदम पर अपमानित करना यही बताने का प्रयास है कि हिंदू भावनाओं की अभिव्यक्ति सख्त मना है। कि हिंदुओं को बराबरी की अनुमति नहीं। हिंदू को केवल पिटने, अपमानित होने और अन्य सभ्यताओं के समक्ष जी–हुजूरी की इजाजत है। वह स्वयं को हिंदू भी नहीं कह सकता। उसे केवल सेक्यूलर कहलाना है। उच्च–वर्गीय हिंदुओं ने यह हीन स्थिति स्वीकार कर ली है, जो ईसाई, इस्लामी और कम्युनिस्ट साम्राज्यवादियों ने लंबे समय से जबरन बना रखी है।

यह हीन–भावना हिंदू नेताओं, बुद्धिजीवियों में इतनी गहरी बैठी हुई है कि हरेक संकट में वे इस्लामी, ईसाई या मार्क्सवादी सहमतों के विरुद्ध एक होने के बदले उस हिंदू से ही कतराते हैं जिसने कुछ सच बोल दिया हो। इसीलिए मूल गोधरा–कांड, जिसने प्रतिहिंसा पैदा की, कभी नाराजगी या न्याय का विषय नहीं बना। किंतु उसके बाद हुई हिंदू–प्रतिक्रिया अंतहीन विषवमन का स्थायी विषय बनी रही है। यह स्वतः नहीं हुआ, न इसे भारतीय जनता का समर्थन है।

यदि हम हिंदू होकर भी दुनिया के सामने खुल कर हिंदुओं की चिंता रखने से बचते हैं, और सेक्युलर दिखना चाहते हैं तो निर्बलता स्पष्ट है। राजनीति में निर्बल नहीं, शक्तिशाली टिकता है। मोदी को ध्वस्त करने की चाह के पीछे हिंदुओं को दबाने और हिंदू दब्बूपन को यथावत रखने की रणनीति है। अब मोदी एक प्रतीक के रूप में हैं, व्यक्ति के रूप में नहीं। ■

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

गरीबों की गिनती में गड़बड़झाला

&'kkrk dekj

देश में गरीबी की गणना करने वाले विभिन्न सरकारी संस्थानों के आंकड़े, जो एक–दूसरे से मेल नहीं खाते, यदि ध्यानपूर्वक खंगालें जाएं, तो यह संख्या 27 करोड़ से अधिक ही नजर आती है। आजादी के बाद जिस तरह से देश में गरीबों की तादाद बढ़ी हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि देश के राजनीतिक नेतृत्व ने विगत 63 वर्षों में गरीबी दूर करने के लिए जो भी योजनाएं बनाईं, वे सतही निकलीं और देश का गरीब अपनी दुर्दशा पर लगातार आंसू बहाता रहा।

गरीबों की संख्या के आंकलन का विचार वर्ष 1957 में आयोजित इंडियन लेबर कॉन्फेंस में उठाया गया। उसी सम्मेलन में देश की गरीबी के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन–यापन की व्याख्या की गई। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव के फलस्वरूप योजना आयोग ने वर्ष 1962 में एक कार्यदल का गठन किया।उस कार्यदल ने पहली बार देश में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। और वर्ष 1960–61 के मूल्यों के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारक–मानकों में कैलारी मानक को भी सम्मिलित किया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए 2,400 कैलोरी आहार और शहरी क्षेत्रों में 2,100 कैलोरी युक्त आहार जुटाने को गरीबी रेखा के मानकों में शामिल किया गया। वर्ष 2004–05 में भी तेन्दुलकर कमेटी ने इसी आधार पर गरीबों की गणना की और पाया कि वर्ष 2004–05 के 27 करोड़ गरीबों के सरकारी आंकड़े में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा 27 करोड़ से बढ़कर अब 37 प्रतिशत हो गया है। दरअसल, इस समिति ने गरीबी का अनुमान लगाने के मापदंडों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया।

केन्द्र सरकार के समक्ष गरीबी के आकलन के लिए कुछ ऐसे निर्धारित आंकड़े हैं, जिनके भंवरजाल में फंसकर वह गरीबों की गणना करने में सफल नहीं हो पा रही। आलम यह है कि वर्ष 1997 में बनी लकड़वाला समिति से लेकर अगस्त 2009 में एन.सी. सक्सेना के नेतृत्व मे गठित कार्यदल की रिपोर्ट तक गरीबी के आंकड़ों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सक्सेना रिपोर्ट की मानें, तो हमारे देश में पौष्टिक आहार न पाने वाले लोगों की संख्या सरकारी तौर पर घोषित संख्या से दोगुनी है। देश के गरीब खाने पर कम और शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च करते हैं।

उधर, वर्ष 2007 में अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में गठित कार्यदल के अनुसार, 77 प्रतिशत जनसंख्या 20 रूपये से कम प्रतिदिन की आय से गुजर–बसर कर रही है। इन आंकड़ों से परेशान सरकार ने नवंबर, 2009 में सुरेश तेन्दुलकर की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया, जिसने अखिल भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 41. 8 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत आंका। ये आंकड़े विश्व बैंक के आंकड़ों के करीब हैं। तेन्दुलकर समिति के अनुसार, उड़ीसा और बिहार दो ऐसे राज्य हैं, जहां सबसे ज्यादा गरीबी है। इस समित ने हर महीने गरीबी रेखा के तहत प्रति व्यक्ति खर्च की जाने वाली राशि का भी पुनर्निर्धारण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि 356.30 रूपये से बढ़ाकर 446.68 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 538.60 रूपये से बढ़ाकर 578. 80 रूपये करने का सुझाव दिया है। इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति दैनिक खर्च की राशि 15 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 19 रूपये आती है।

इस सबके बावजूद केन्द्र सरकार ने अब बीपीएल राशन पर रोक लगाने का फैसला लिया है। कारण यह है कि योजना आयोग के अनुसार देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.1 करोड़ रूपये है, जबकि राज्यों द्वारा 10.68 करोड़ बीपीएल राशन कार्ड आवंटित किए गए हैं। साफ है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भी अब इन गरीबों को राशन मुहैया नहीं होगा।

गरीबों की संख्या का सही आकलन न कर पाने का सबसे अधिक नुकसान गरीबों को ही है। इसके कारण बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य, जहां आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, विकास की दौड़ में और अधिक पिछड़ रहे हैं। जिस मात्रा में देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गांव से पलायन बढ़ता जा रहा है, निस्संदेह सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश भूखों और गरीबों का देश कहलाएंगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो डॉलर प्रतिदिन की आय वाले व्यक्ति को गरीब समझा जाता है। इस कसौटी पर कसें, तो भारत की आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के तहत आ जाएगी। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकार अभी तक यह भी निर्णय नहीं कर पाई है कि भारतवर्ष में भूखों और गरीबों की संख्या कितनी है। राष्ट्र संघ के एक आकलन के अनुसार, विश्व में सबसे अधिक भूखे, नंगे और गरीब भारतवर्ष में हैं।

दरअसल, हमारे देश में गरीबों की गणना आंकने के मापदंड विभिन्न संस्थाओं द्वारा भिन्न–भिन्न रखे गए हैं, जिसके कारण गणना में प्रायः अंतर आ जाता है। दिक्कत यह है कि इस अपुष्ट आकलन के कारण गरीबों के लिए जो भी

शेष पृष्ठ..... पर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो डॉलर प्रतिदिन की आय वाले व्यक्ति को गरीब समझा जाता है। इस कसौटी पर कसें, तो भारत की आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के तहत आ जाएगी। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकार अभी तक यह भी निर्णय नहीं कर पाई है कि भारतवर्ष में भूखों और गरीबों की संख्या कितनी है। राष्ट्र संघ के एक आकलन के अनुसार, विश्व में सबसे अधिक भूखे, नंगे और गरीब भारतवर्ष में हैं।

भाजपा नेताओं ने दी नानाजी को श्रद्धांजलि

देश के पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी नानाजी देशमुख को देश का 'रील हीरो' नहीं 'रियल हीरो' के खिताब से नवाजा था। उनके त्रयोदश संस्कार में जुटी नामचीन हस्तियों की जमात बहुत पहले अब्दुल कलाम द्वारा दिए गए इस खिताब को सच साबित कर रही थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे नानाजी देशमुख ने सियासत में रहते हुए भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी को मजबूत किया तो उम्र के छठे दशक के बाद सियासत को खुदा हाफिज करके इस कदर सामाजिक सेवा की कि दूसरे सियासी दलों के नेता ही नहीं, नामचीन हस्तियां भी उनकी मुरीद हो गई। उसी मील के पत्थर को नमन करने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री सर्वश्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आरएसएस के मदन दास देवी समेत राजनीति, सामाजिक हस्तियों के साथ–साथ साधू और आमजन का हुजूम जिस कदर नानाजी की कृति को निहार कर धन्य–धन्य हो रहा था, उससे यह संदेश साफ था कि नानाजी न जाने कब तक जीवंत बने रहेंगे।

शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह नौ बजे से ही नानाजी के प्रकल्प दीनदयाल शोध संस्थान के उद्यमिता विद्यापीठ के परिसर में भंडारे की शुरूआत हुई। उनके दत्तक पुत्र एवं डीआरआई के प्रधान सचिव भरत पाठक ने कर्मकांड की औपचारिकता पूरी की। भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने नानाजी के अंतिम क्षणों को याद किया तो बरबस आंसू छलक आए। उन्होंने उद्यमिता विद्यापीठ की निदेशिका डा. नंदिता पाठक को नानाजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आत्मसात करने की सलाह दी। ■

नानाजी की याद में फफक पड़े आडवाणी

चित्रकूट, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी नानाजी देशमुख से जुड़ी यादों में भावुक हो ऐसा डूबे कि देर तक फफक कर रोते रहे।

आंखों के रास्ते निकला दिल का दर्द रूमाल में समेटने की कोशिश करते हुए जब उन्होंने रुंधे गले से कहा कि नानाजी के ही मंत्र से गांवों में खुशहाली आयेगी और पं.दीनदयाल जी का अंत्योदय का सपना साकार होगा तो बगल में बैठे संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख मदनदास देवी ने सहमति व्यक्त कर दी।

नानाजी के त्रयोदशी भोज में भाजपा नेता आडवाणी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्याह्न करीब एक बजे दो हैलीकाप्टरों से आरोग्यधाम पहुंचे। वहां से कार द्वारा सीधे उद्यमिता विद्यापीठ स्थित आयोजन स्थल पर आ गये। वहां पर संघ के वरिष्ठ प्रचारक मदनदास देवी, सुरेश सोनी, मध्य प्रदेश सरकार के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्त, संसदीय कार्य मंत्री डा.नरोत्तम, सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, राज्यसभा सदस्य प्रभात झा, उप्र सरकार के पूर्व मंत्री हरीकिशन श्रीवास्तव सहित कई प्रमुख राजनीतिज्ञ व संघ परिवार से जुड़े वरिष्ठ लोग पहले से ही मौजूद थे।

भाजपा नेता आडवाणी जी जब श्रद्धासुमन अर्पित करने नानाजी के करीब 12 फुट उंची प्रतिमा के समीप पहुंचे तो आंखें नम हो गयीं और देर तक एकटक उनका चित्र देखते रहे। इसके बाद उन्होंने सबके साथ नानाजी के कार्यों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव श्री अभय महाजन से बीच–बीच में जानकारी भी हासिल की।

वापस पंडाल में पहुंचते ही डीआरआई से जुड़ी डा.नंदिता पाठक ने जब उप प्रधानमंत्रित्वकाल के दौरान मझगवां गांव में हुए कार्यक्रम की याद दिलायी तो वे फफक पड़े।

काफी देर बाद अपने को सहज करने का प्रयास करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मैंने नानाजी की अंगुली पकड़कर बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद तो उन्होंने आपातकाल के दौरान के नानाजी से जुड़े कुछ संस्मरण भी सुनाये।

चर्चा नानाजी के रचनात्मक कार्यों की ओर मुड़ी तो आडवाणी ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने जो दरिद्र नारायण को आराध्य मानते हुए समाज के आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सपना देखा था, वह नानाजी के ही ग्रामोदय प्रयोग से ही पूरा होगा।

इस बीच भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नानाजी से तो सदैव पितामह तुल्य आशीष और मार्गदर्शन मिलता रहा। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान मिले नानाजी के विकास संबंधी सुझावों का जिक्र किया। आडवाणी के कुछ पूछने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नानाजी के कार्यों के विस्तार में सरकार पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी करती रहेगी।

प्रसाद ग्रहण करने की बात आयी तो सभी नेताओं ने भी आम लोगों की तरह जमीन पर बैठकर पत्तल में भोजन ग्रहण किया। करीब डेढ़ घंटे परिसर में बिताने के बाद आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी तो हेलीकाप्टर से चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम चार बजे तक रुके रहे। सायंकाल उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री श्री प्रसाद भी नानाजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और भोज में शामिल हुए।■

युवा जागर यात्रा, नागपुर

भाजपा पृथक राज्य विदर्भ का समर्थन करेगी : गडकरी

गत 14 मार्च को यशवंत स्टेडियम, नागपुर में आयोजित एक विशाल 'युवा जागर यात्रा' की रैली को सम्बोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने उपस्थित विशाल समूह को विश्वस्त किया कि कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार जब कभी भी तेलंगाना बिल संसद में पेश करेगी तो

भाजपा एक अलग विदर्भ राज्य का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भाजपा केवल तेलंगाना बिल को ही सदन में पेश नहीं होने देगी बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि यूपीए सदन में अलग से विदर्भ राज्य के गठन का बिल भी शामिल करे।

श्री गडकरी ने अलग तेलंगाना राज्य के गठन के लिए संकट खड़ा कर दिया, उसके लिए यूपीए सरकार की घोर आलोचना की और कहा कि इससे स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई है उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भी इस बात के लिए निंदा की कि उन्होंने विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र के विकास कार्य में जरा रूचि नहीं दिखाई है। उन्होंने यह भी कहा विदर्भ राज्य का गठन निश्चित ही व्यवहार्य है क्योंकि यहां आर्थिक दृष्टि से कोयला, खनिज और बिजली उत्पादन की गहरी क्षमताएं मौजूद हैं। परन्तु राज्य सरकार की योजना और गलत नीतियों के चलते यह पूरा क्षेत्र ही विकास कार्य में पिछड़ गया है।

रैली को सम्बोधित करते हुए लोकसभा में भाजपा के उप–नेता श्री गोपीनाथ मुण्डे ने दो मराठी भाषी राज्यों के गठन की वकालत की। उन्होंने कहा कि जब हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कई मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है यदि दो मराठी भाषी मुख्यमंत्री कार्यभार संभालें।

श्री मुण्डे ने यह भी कहा कि नागपुर पहले मध्य प्रदेश की राजधानी थी जिसके मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ला थे, इस समय नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है जहां विधान भवन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री, उप–मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले और विधायकों के हॉस्टल तथा राज्यपाल भवन आदि जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।

श्री मुण्डे ने स्मरण कराया कि भाजपा–नीत एनडीए सरकार ने छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखण्ड जैसे छोटे राज्यों का गठन किया था।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और झारखंड के उप–मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने भी छोटे राज्यों के गठन की हिमायत की और कहा कि इन नए राज्यों के गठन के बाद इनकी प्रतिव्यक्ति आय, वार्षिक बजट और बिजली उत्पादन में कई गुणा वृद्धि हुई है।

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री एकनाथ खाडसे ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सदा ही छोटे राज्यों के गठन का समर्थन करती आई है। हमने छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तराखंड का समर्थन किया। मैं विदर्भ राज्य के गठन के लिए केन्द्र को पत्र लिखूंगा। इससे हम क्षेत्र के लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

अन्य नेताओं में श्री पाण्डुरंग फुंडकर, पूर्व सांसद श्री जम्बुवंत राव घोते, श्री बनवारी लाल पुरोहित और अनेक पूर्व तथा वर्तमान विधायक रैली में शामिल थे।

पृथक विदर्भ के मुद्दे पर तेज हुआ विरोध प्रदर्शन

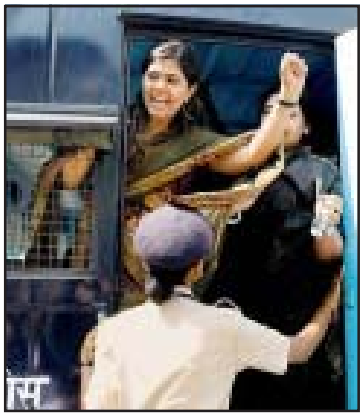

अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर विरोध–प्रदर्शन तेज होने लगे हैं। समर्थकों ने नागपुर में रिजर्व बैंक चौराहे और गोलिबर चौक से जेल भरो आन्दोलन की शुरुआत की।

इस बीच मुंबई में 25 भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर गिरफ्तारियां दी। विधानसभा में विपक्ष के नेता पांडुरंग फुंदकर, विधायक सुधीर मुंगंनतिवार और देवेन्द्र फड़नवीस भी अलग विदर्भ राज्य की मांग करने वालों में शामिल थे। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने के मांग की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनाई दी, जब भाजपा सदस्यों ने तत्काल इसके समर्थन में प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए सदन से वाकआउट कर दिया। भाजपा सदस्यों ने आज सदन में विदर्भ को अलग राज्य बनाने के लिए जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि 1956 की नागपुर संधि का कई बार उल्लंघन हो चुका है। 1956 की नागपुर संधि के जरिए ही विदर्भ क्षेत्र को महाराष्ट्र में शामिल किया गया था। भाजपा विधायक सुधीर मुंगांतीवार ने कहा कि किसानों की आत्महत्या, निम्न रोजगार आदि समस्याओं के कारण विदर्भ सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ गया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन भी चलाया। इसमें कई विधायकों को मुंबई में गिरफ्तार भी किया गया है।

आम आदमी पर कांग्रेस का हमला जारी : भाजपा

जहां भारत के लोग बढ़ती कीमतों के नीचे सिसक रहे हैं, वहीं आम आदमी पर कांग्रेस का हमला बदस्तूर जारी है। लोगों के घावों पर मरहम लगाने की बजाय कांग्रेस उन पर नमक छिड़कने पर तुली हुई है। पहले, केन्द्रीय बजट और

अब दिल्ली स्टेट के बजट ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। केन्द्रीय बजट के द्वारा पैट्रोल, डीज़ल, उर्वरकों के मूल्य बढ़ाए गए, जिनका मुद्रास्फीति पर प्रपाती प्रभाव पड़ा और अन्य करों में भी वृद्धि हो गई। साथ ही सेवा कर ने भी आम आदमी पर भारी बोझ डाल दिया है।

अब दिल्ली सरकार ने एक ही झटके में डीज़ल के मूल्य 2.67 रूपए प्रति लिटर और कुकिंग गैस के मूल्य 40 रूपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए हैं। इसके कारण उन लोगों की कमर और बुरी तरह टूट जाएगी, जो तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण पहले से ही कठिनाई झेल रहे हैं। जब भी कीमतों पर चर्चा होती है तभी कांग्रेस पार्टी आमतौर पर राज्य सरकारों पर और खासतौर पर राजग पर आरोप लगाती है। भाजपा जानना चाहती है कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों को सलाह क्यों नहीं दे रही है तथा कीमतों को नीचे क्यों नहीं ला रही है? भाजपा उक्त बजट प्रस्तावों की घोर निंदा करती है और इसके कारण आम आदमी पर बढ़े बोझ को तुरंत वापस लेने की मांग करती है।

अब देश के लोगों ने महसूस कर लिया है कि मूल्यवृद्धि कांग्रेस की जन–विरोधी नीतियों का ही परिणाम है – चाहे वह आयात–निर्यात हो, राजकोषीय मामला हो, खाद्य स्टॉक का प्रबंधन हो तथा वायदा बाजार आदि के बारे में लिए गए निर्णय हों। थोक मूल्य सूचकांक दो अंकों में प्रवेश कर रहा है, खाद्य पदार्थों के मूल्य लगभग 16 प्रतिशत ऊंचे हो रहे हैं और राजकोषीय घाटा 7 प्रतिशत के आस–पास है। ये सभी बातें मूल्यों में और अधिक वृद्धि करने वाली हैं।

यह विडंबना ही है कि जहां धान पैदा करने वाले को 11 रूपए प्रति कि.ग्रा. की प्राप्ति हो रही है वहीं उपभोक्ता को इसके लिए 40 रूपए प्रति कि.ग्रा. चुकाने पड़ रहे हैं। इसका न्यायोचित मूल्य 16–20 रूपए प्रति कि.ग्रा. होना चाहिए। जिस चीनी का अब हम उपयोग कर रहे है, उसका उत्पादन गत वर्ष हुआ था। इसके लिए किसानों को 16 रूपए प्रति कि.ग्रा. प्राप्त हुए थे, जिसके लिए उपभोक्ता अब 45 रूपए प्रति कि.ग्रा. अदा कर रहा है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी के शासन में जनता को खुले आम लूटा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सट्टेबाजों के साथ पूरी साठगांठ है।

भाजपा द्वारा शुरू किए गए देशव्यापी आंदोलन को आम लोगों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। मूल्यवृद्धि के विरुद्ध 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों के हस्ताक्षर पहले ही एकत्रित हो चुके हैं और 5 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर देशभर से और आगे एकत्रित किए जाएंगे। 21 अप्रैल, 2010 को लोगों की आम लामबंदी की तैयारियां जोर–शोर से चल रही हैं। उस दिन मूल्यवृद्धि के विरोध में 10 लाख से भी अधिक लोग संसद की ओर कूच करेंगे।

दिल्ली

गौमांस के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान खिलाड़ियों को गौमांस परोसे जाने संबंधी मसले पर दिल्ली विधानसभा में खासा हंगामा हुआ। पक्ष–विपक्ष ने एक–दूसरे पर जमकर आरोप–प्रत्यारोप लगाए व नारेबाजी की।

विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दिल्ली में गौमांस परोसे जाने पर प्रतिबंध लगा होने के बावजूद सरकार द्वारा गुपचुप तरीके से उक्त मांस परोसे जाने के संबंध में अपनी सहमति देने का आरोप लगाया। इस मामले में विपक्ष ने जहां सदन से वाकआउट किया वहीं हंगामे के चलते अध्यक्ष डा. योगानन्द शास्त्री को सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी।

विधानसभा में नियम 280 के विशेष उल्लेख के दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान खिलाड़ियों को गौमांस परोसे जाने का मामला उठाते हुए इस संबंध में हाल ही में मुख्य सचिव दिल्ली सरकार राकेश मेहता द्वारा दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। प्रो. मल्होत्रा का कहना था कि दिल्ली में जबकि गौ हत्या, उसका मांस परोसने या रखने तक पर प्रतिबंध है और इस संबंध में कानून भी बना हुआ है, ऐसे में मुख्य सचिव द्वारा इस तरह का बयान देना कानून का उल्लंघन है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से जवाब देने को कहा। प्रो. मल्होत्रा द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का सदन में मौजूद भाजपा विधायकों ने एक स्वर से समर्थन किया और इसे लोगों की धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए कहा कि गौमांस परोसा गया तो इसका सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ विधायक प्रो. जगदीश मुखी ने कहा कि यदि गौमांस परोसा गया तो खेल नहीं होने दिए जाएंगे। शोर–शराबे के दौरान प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में आईपीएल मैचों व

कामनवैल्थ गेम्स से पूर्व आयोजित की जा रही विभिन्न चैम्पियनशिप जिनमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जब उनमें से किसी ने गौमांस नहीं मांगा तो कामनवैल्थ गेम्स में यह मांस क्यों परोसा जाए? भाजपा सदस्यों ने इस पर विदेशी दबाव होने का सरकार पर आरोप लगाया।

बिहार

भाजपा का शंखनाद, रामराज्य की ओर बढ़ रहा बिहार

भारतीय जनता पार्टी ने बेलगाम महंगाई के खिलाफ पटना में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अनंत कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया

कि बिहार को दोबारा जीतने के बाद दिल्ली फतह में जुट जाइए। यूपीए सरकार नहीं चलेगी। यह उल्टा–पुल्टा एलायंस है। मध्यावधि चुनाव होना ही है। सम्मेलन ने विधानसभा चुनाव में भाजपाई मुद्दों व रणनीति को स्पष्ट किया। पहले चरण में महंगाई के बहाने पार्टी गांव–गांव, घर–घर जायेगीय केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर जुटाएगी दूसरे चरण में अपनी सरकार की उपलब्धियों तथा बिहार के प्रति केंद्र के यूपीए (संप्रग) सरकार के सौतेले व्यवहार से लोगों को वाकिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण का अभियान चलो गांव की ओर है। बूथ स्तर से एक करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य हैं। 21 अप्रैल को संसद के घेराव में बिहार की खासी भागीदारी होगी।

भाजपा नेता श्री कुमार ने दावा किया कि केंद्र में अगली सरकार राजग की होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को उन्होंने महासंग्राम बताया जिससे केंद्र सरकार के खात्मे की शुरूआत होगी। बिहार की राजग सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पहले जंगल राज था। अब यह राज्य रामराज्य की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राधामोहन सिंह ने कहा–महंगाई की जड़ में चावल, दाल, चीनी गेहूं घोटाला है। जब–जब कांग्रेस आती है, महंगाई लाती है। भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बना है। वाजपेयी सरकार ने महंगाई को नियंत्रित किया था। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अनुसार मजाक का पात्र रहा बिहार अब कई क्षेत्रों में प्रणेता व पथप्रदर्शक की भूमिका में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सावधान किया–बंटाईदारी बिल का हौव्वा खड़ा कर भ्रम फैलाया जा रहा है। हमें कांग्रेस, राजद, लोजपा से सावधान रहना है। सम्मेलन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती किरण घई ने भी विचार व्यक्त किए।

स्वास्थ्य मंत्री नंदकिशोर यादव, श्रम संसाधन मंत्री अवधेश नारायण सिंह, सहाकारिता मंत्री गिरीराज सिंह, पशुपालन मंत्री रामनारायण मंडल और पीएचईडी मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी विचार व्यक्त किए।

अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ रैली

रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट का देश को असंगठित करने का प्रयास

अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ मंच ने 10 मार्च को एक विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें पूरे देश से भारी संख्या में लोग रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का विरोध करने के लिए एकत्र हुए। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती

सुषमा स्वराज ने कहा कि भाजपा रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का विरोध करती रहेगी क्योंकि इस आयोग ने अल्पसंख्यक समुदाय के आरक्षण की सिफारिश की है जिसका परिणाम यह होगा कि समाज बंट कर रह जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा षड्यंत्र है जिसे कांग्रेस बहुत लम्बे समय से चला रही है और भाजपा कभी भी पिछड़े वर्गों के साथ यह अन्याय नहीं होने देगी। हम पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे जिसे हम सदन के अंदर और बाहर जारी रखेंगे।

श्रीमती स्वराज ने कहा कि जिन लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने के नाते खूब लाभ उठाया आज वे पिछड़े वर्ग के उन लोगों का हक छीनना चाहते हैं जिसे इन लोगों ने बड़े लम्बे समय तक संघर्ष करने के बाद हासिल किया।

राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मजहब बदलने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन हिन्दू लोगों ने अन्य मजहबों की शरण ले ली, कांग्रेस उन्हें मजहब बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे आरक्षण का लाभ भी

उठाएं और अल्पसंख्यक होने वाले लाभ भी उठाएं।

श्री जेटली ने कहा कि संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई प्रावधान है और अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करना उनके साथ अन्याय करना होगा जिन्होंने सदियों तक कठिनाइयों का सामना किया है। यह बहुत विचित्र होगा कि उन्हें दो–दो अधिकार प्राप्त हो जाएं– उन्हें आरक्षण का लाभ भी मिले और अल्पसंख्यक लाभ भी प्राप्त हों।

उन्होंने आगे कहा कि मिश्रा रिपोर्ट समाज को समाज के अंदर बांटने का षड्यंत्र है और यह कमजोर वर्गों के अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र है।

दोनों नेताओं ने कहा कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान उन लोगों को तरक्की देना है जिन्हें सदियों तक इन सुअवसरों से वंचित रखा गया था और यह भी तय किया गया था कि मजहब के आधार पर ये प्रावधान नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा भाजपा मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, सभी मुस्लिम हमारे भाई हैं और उनकी चिंता करना हमारा कर्त्तव्य है क्योंकि हम सभी भारतीय हैं, परन्तु यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि साम्प्रदायिक सिफारिश का कार्यान्वयन निश्चित ही 'खतरनाक और आत्महत्या' करने जैसा होगा और इससे देश फिर विभाजन की ओर बढ़ेगा।

भाजपा पूर्व अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण ने इसे विडम्बना ही बताया कि उन समुदायों के आरक्षण की बात की जा रही है, जिनमें कभी भी जाति प्रथा थी ही नहीं। इस अवसर पर श्री अनंत कुमार एवं अन्य कई भाजपा नेता उपस्थित थे।

मध्य प्रदेश

मप्र सरकार मकोका की तर्ज पर बनाएगी नया कानून

आतंकवाद के खिलाफ महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर नया कानून बनाएगी। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने हाल ही में राज्य विधान सभा में इसके लिए एक विधेयक पेश किया। गुप्ता ने पिछले राज्य विधान सभा में मप्र आतंकवादी एवं PPNsnd गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2010 प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार ने इससे पहले वर्ष 2007 में भी इसी तरह का एक कानून पास कर केन्द्र सरकार को भेजा था लेकिन केन्द्र सरकार ने उस समय यह कानून प्रदेश सरकार को वापस कर दिया था। गृह मंत्री के अनुसार प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ कोई प्रभावी कानून नहीं होने से लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी तथा केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम की सलाह के अनुसार पूर्व के कानून में संशोधन कर राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा पारित कानून के तहत नया विधेयक तैयार कर विधान सभा में पेश किया है। उन्होंने बताया कि राज्य विधान सभा में पारित करने के बाद इस विधेयक को मंजूरी के लिए केन्द्र के पास भेजा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए संशोधनों के बाद अब इसे केन्द्र से अनुमति मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नए कानून में जिन अपराधों को शामिल किया गया है उनमें आतंकवादी गतिविधियों के अलावा विस्फोट करने के इरादे से घुसपैठ करना, नशीले पदार्थो की तस्करी तथा फिरौती के लिए अपहरण आदि शामिल हैं। विधेयक में इन अपराधों की रोकथाम के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं जिनमें आतंकवादी गतिविधियों में किसी की मौत होने पर आरोपी को मृत्यु दंड दिए जाने तक का प्रावधान है। आतंकी गतिविधियों के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष अदालतों के गठन के अलावा आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ भी कडे प्रावधान इस कानून में किए गए हैं।

दिल्ली

'यूथ फॉर बीजेपी' सम्मेलन - एक रिपोर्ट

14वीं लोकसभा के चुनावों के तुरंत बाद 'यूथ फार बीजेपी'– एक युवा संगठन का गठन किया जिसका प्रमुख उद्देश्य युवाशक्ति को भाजपा के साथ जोड़कर पार्टी को शक्तिशाली बनाना है। यह सम्मेलन दिल्ली प्रदेश भाजपा मुख्यालय में 21 मार्च 2010 को आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन में 150 से अधिक युवा वालंटियरों ने भाग लिया जिनमें व्यावसायिक, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता, मैनेजमेंट से जुड़े विद्यार्थी तथा अनेक क्षेत्रों के युवा शामिल थे। इन

सभी युवाओं ने सम्मेलन में पार्टी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए 'राष्ट्र प्रथम', फिर पार्टी तथा अंत में स्वयं व्यक्ति का एक सोद्देश्य नारा दिया और स्वयंसेवी बन कर कार्य करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

इस अवसर पर 'यूथ फार बीजेपी' के संगठन समिति की सदस्य श्री कुणाल ने एवीएस की नवीनतम टेक्टनालाजी का प्रयोग करते हुए एनडीए सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जिसमें तत्कालीन शासन की विज्ञान और तक्नालॉजी, शिक्षा, ग्रामीण विकास, बिजली, कृषि आदि अनेक क्षेत्रों का विकास दिखाया गया।

सांसद एवं 'कमल संदेश' के सम्पादक श्री प्रभात झा ने

समारोह की अध्यक्षता की। अन्य प्रमुख व्यक्तियों में रा.स्व.सं. के वरिष्ठ चिंतक श्री आलोक कुमार, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री (संगठन) श्री विजय शर्मा और पार्टी के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह–संयोजक श्री आर.एन पाण्डेय भी उपस्थित थे।

श्री प्रभात झा ने अपने उद्‌बोधन में 'राष्ट्र प्रथम, फिर पार्टी और अंत में स्वयं व्यक्ति' जिसे 'यूथ फार बीजेपी' ने अपना नारा बनाया है, आज की सबसे बड़ी सोच है। भाजपा ने बाह्य खतरों एवं आंतरिक अशांति तथा प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए सदा ही इस नारे को अपना प्रमुख उद्देश्य बना कर देश की सेवा में समर्पित किया है। यही भाजपा की सोच है। सम्मेलन में एक स्वयंसेवी ने प्रश्न किया कि 'आप क्यों भाजपा को पसंद करते हैं?' प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री झा ने कहा कि भाजपा ही एक पार्टी है जो शब्द और भाव दोनों में 'राष्ट्रवादी' एजेण्डे को अपने सामने रखती हैं।

रा.स्व.सं के प्रमुख चिंतक श्री आलोक कुमार ने भी अपने उद्‌बोधन के अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर बताया कि भाजपा ही एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी है और यही पार्टी 'राष्ट्र प्रथम', फिर पार्टी और अंत में स्वयं व्यक्ति' को लेकर चलती है। उन्होंने इसके समर्थन में उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि 1971 के युद्ध में श्री वाजपेयी ही प्रथम और एक मात्र नेता थे जिन्होंने कहा था कि इस युद्ध में 'पूरा भारत श्रीमती गांधी के नेतृत्व में उनके पीछे खड़ा है।''

दिल्ली प्रदेश के महामंत्री (संगठन) श्री विजय शर्मा ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और दिल्ली की राजनैतिक प्रणाली और देशभर में चल रही प्रणाली को सामने रखते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को यह कहना कि वह कोई एक निश्चित कार्य करे– ठीक नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा कोई भी उत्तरदायित्व खुशी से निभाना चाहिए जिसे वह कर सकता है।

अंत में श्री विजय शर्मा ने सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रगट किया तथा कोर समिति के सदस्यगण सर्वश्री सुमित भसीन, मुरारी चतुर्वेदी, विनीत पठानिया, देवेन्द्र रावत, सुमन सर्दवाल, रविन्द्र सैनी, मृत्युंजय कुमार और शशिकांत को भी धन्यवाद दिया।■

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कोइराला का निधन

नेपाल की राजनीति में खास स्थान रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के एक विश्वसनीय मित्र श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का 20 मार्च को काठमांडू में निधन हो गया। नेपाल के पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके 87 वर्षीय कोइराला पिछले कुछ माह से बीमार थे और उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। नेपाल में करीब एक दशक से चले आ रहे सशस्त्र संघर्ष को समाप्त कर माओवादियों को मुख्यधारा की राजनीति में लाने तथा शांति प्रक्रिया की अगुवाई में कोइराला की उल्लेखनीय भूमिका थी। करीब एक दशक के सशस्त्र संघर्ष में 16,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का राजनीतिक सफर छह दशक से □ी ज्यादा लंबा रहा। वह शून्य से शुरुआत कर शिखर पर पहुंचने वाले नेताओं में रहे। देश–विदेश के नेताओं ने नेपाली कांग्रेस के बुजुर्ग नेता के निधन पर शोक जताया। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने श्री कोईराला के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ने श्री कोइराला को 'नेपाल के सबसे बड़े और दक्षिण एशिया के वयोवृद्ध राजनेता' के तौर पर याद किया। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरूआत मजदूर संघों के आंदोलन के साथ की थी और अपना पूरा राजनीतिक जीवन लोगों के कल्याण संबंधी कार्यों में बिताया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कोईराला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें 'बड़े कद का राजनीतिक नेता बताया। श्री गडकरी ने कहा कि श्री कोइराला भारत के महान मित्र थे और सच्चे लोकतांत्रिक थे।

श्री कोइराला का अंतिम संस्कार बागमती नदी के तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ हिंदू परंपराओं के मुताबिक किया गया। उनकी बेटी सुजाता कोइराला ने एक असामान्य धार्मिक परंपरा के तहत अपने पिता के शव को मुखाग्नि दी। नेपाली सेना ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। भारत का एक उच्च शिष्टमंडल इस मौके पर वहां मौजूद था। भाजपा की ओर से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह स्व. कोइराला के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ■

पृष्ठ ..... का शेष

योजनाएं बनाई जाती हैं, वे सभी गड़बड़ हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो भी नीतियां गरीबों के लिए बनती हैं, वे गरीबों के लिए लक्षित नहीं होती, बल्कि सरकारी आंकड़ों का पेट भरने के लिए बनाई जाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार सही गणना करे, पर केवल गणना ही न करती रहे। आज तक गणनाएं होती रहीं योजनाएं बनती रहीं, गरीबी दूर करने के नारे लगते रहे, पर गरीबी प्रतिवर्ष बढ़ती रही।

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर मे सरकार ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में गरीबों की संख्या चार करोड़, 40 लाख बढ़ गई है। दूसरी तरफ, विश्व के करोड़पतियों में भारतीयों की संख्या बढ़ रही है। फौर्ब्स पत्रिका के अनुसार, पिछले एक वर्ष में भारत के 100 अमीर परिवारों की संपत्ति छह लाख करोड़ रूपये से बढ़कर 13 लाख करोड़ रूपये हो गई है। यही स्थिति रही, तो कुछ समय के बाद विश्व में सबसे अधिक करोड़पति भारत में होंगे और सबसे अधिक भूखे–नंगे लोग भी।

हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि देश में बढ़ते अपराध, नक्सलवाद और माओवाद का एक बड़ा कारण गरीबी एवं आर्थिक विषमता है। ऐसा न हो कि सरकार आंकड़ों के मकड़जाल में उलझी रहे और देश अपराध व नक्सलवाद की भट्‌ठी में समा जाए। ■ *(लेखक हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं)*

कांग्रेस शासन सदैव महंगाई की मार का प्रतीक रहा है : भाजपा

Hkkजपा प्रदेश उत्तराखंड ने 14 मार्च को एक विशाल महंगाई विरोधी रैली का आयोजन किया जिसमें विभिन्न भाजपा नेताओं ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जब–जब कांग्रेस ने केन्द्र की सत्ता संभाली है, तब–तब मुद्रास्फीति बेहिसाब बढ़ती चली गई और आम आदमी इस महंगाई से निरंतर त्रस्त होता चला गया। अतः आज जब आम आदमी कमरतोड़ महंगाई से दुखी है तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों का भण्डाफोड़ करें।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री अनंत कुमार ने अपने भाषण में कहा कि समय आ गया है कि लोग वर्तमान कांग्रेस–नीत केन्द्रीय कुशासन के

प्रति अपनी आवाज बुलंद करें तथा भाजपा भी इस विषय पर चुप नहीं बैठी रहेगी। उन्होंने कहा भाजपा देश की सभी राजधानियों में 21 अप्रैल को विशाल रैलियों का आयोजन करेगी जिसमें लोग भारी संख्या में आकर इन्हें सफल बनाने में अपना योगदान करें।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने पिछले आम चुनावों में सत्ता में आने के बाद आसमान छूती महंगाई को 100 दिनों के अंदर काबू में लाने की बात कही थी, परन्तु आज तो स्थिति न केवल विपरीत है, बल्कि लोगों के कष्ट निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बढ़ती मुद्रास्फीति पर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रही है जिसमें सभी लोग बढ़चढ़कर अपना योगदान दें।

रैली को सम्बोधित करते हुए उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी महंगाई पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार तथा हमारी पार्टी निरंतर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार की जन–विरोधी नीतियों का विरोध करती रहेगी। उत्तराखंड जैसी नवगठित राज्य भी इस बेमिसाल महंगाई की मार से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार ने तो हमारे बार–बार अनुरोध करने पर भी हमारे राज्य के चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी के तेल आदि का कोटा काट दिया है। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। उधर राज्य में कांग्रेसी सांसद हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और राज्य को बदहाल छोड़ रखा है।

रैली में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भुवनचन्द्र खण्डूरी, श्री बिशन सिंह चूफल तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी सम्बोधित किया। ■

कर्नाटक

महंगाई के विरोध में प्रदर्शन

सीएम-मंत्री सड़क पर

रोजमर्रा की चीजों के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने में केन्द्र की कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की विफलता के विरोध में मुख्यमंत्री बी.एस. येड्डियूरप्पा, सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के मंत्री व विधायक सड़कों पर उतरे। उन्होंने महात्मा गांधी मार्ग से राजभवन तक साईकिल रैली निकालकर केन्द्र सरकार की नाकाम आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद राज्यपाल हंसराज भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा।

सुबह नौ बजे मुख्यमंत्री बी.एस. येड्डियूरप्पा व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के.एस. ईश्वरप्पा के नेतृत्व में पार्टी के मंत्रियों व विधायकों की साइकिल रैली महात्मा गांधी मार्ग से राजभवन पहुंची। रैली के दौरान भाजपाई नेताओं ने अपनी बांहों पर काली पट्टियां लगा रखी थीं। प्रदर्शनकारियों ने केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों व महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रहने के खिलाफ नारे लगाए। आम दिनों में कार में घूमने वाले मुख्यमंत्री, मंत्रियों व विधायकों ने साइकिलों पर सवारी करने की होड़ सी लग गई।

के.एस. ईश्वरप्पा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देशभर में आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके बावजूद केन्द्र सरकार इस तरफ ध्यान तक नहीं दे रही है। केन्द्र की इन नीतियों के खिलाफ भाजपा ने 21 अप्रैल को दिल्ली चलों कार्यक्रम रखा है। आज मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों व विधायकों ने काली पट्टी लगाकर सांकेतिक धरना दिया है लेकिन आने वाले दिनों में महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। ■